NEET Bulletin Helpline No.
8800265682
Completely NEET Counselling Guidance specially for
MBBS BDS BAMS BHMS BUMS
B.Sc Nursing GNM D./ B. Pharma
BPT MPT D/BMLT D.Optometry
OT Technician Clinical Research
B.Sc Ag. Micro Bio Bio Chem
Bio tech. BNYS etc.

R.N.I.NO.-UPHIN/2011/41608

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

विजडम इंडिया

निर्भीक और बेबाक अभिव्यक्ति

EMAIL: sheelshukla100@gmail.com

लखनऊ से प्रकाशित

वर्ष: 15 अंक: 324 लखनऊ, गुरुवार 23 जुलाई 2026 मूल्य: 02 रुपये पृष्ठ- 08

मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास

सीएम मोहन यादव ने बताया गोल्डन डे, कहा- अब सबको मिलेगा समान अधिकार

मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के उस विजन के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डा. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था...

नई दिल्ली ((एजंसी) मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विरोध के बीच श्यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विपक्षी विधायक चाहते थे कि बिल को चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएय हालाँकि, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा ध्वनि मत से बिल पारित करने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे सुनहरा दिन बताया और कांग्रेस पार्टी की गलत सोच की आलोचना की। यादव ने मीडिया से कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए सचमुच एक सुनहरा दिन है।मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना श्एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेताश के उस विजन के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था... यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा। मैं पूरे राज्य को बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि श्वे हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंटवारा क्यों पैदा करना चाहते हैं? कांग्रेस की इसी गलत सोच के कारण ही आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ था।

यह बिल किस बारे में है?

यह बिल श्तीन तलाकश और शनिकाह हलालाश को अपराध घोषित करेगा, बहुविवाह पर रोक लगाएगा और लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को एक महीने के भीतर रजिस्टर कराना जरूरी बनाएगाय ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने तक की जेल हो सकती है। इसमें सभी समुदायों के लिए एक ही जीवनसाथी रखने (मोनोगैमी) का नियम भी शामिल है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा जीवित जीवनसाथी नहीं रख सकता। इसके अलावा, शहरी इलाकों में डच ई–नगरपालिका पोर्टल के जरिए शादियों और तलाकध का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ग्रामीण इलाकों में, रजिस्ट्रेशन का काम ैक्ड द्वारा नगर पालिकाओं या पंचायतों के जरिए किया जाएगा। साथ ही, बिल में निकाह हलाला को सजा–योग्य आपराधिक अपराध माना गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (न्ब्) के ड्राफ्ट को मंजूरी दी, जिसे सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किया जाना था। सोमवार को स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के यह कहने के बाद कि इस मामले पर अगले दिन चर्चा होगी, मंगलवार को बिल को फिर से पेश किया गया। यह ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई (रिटायर्ड) कमेटी ने तैयार किया था और पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा था।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली ((एजंसी) नई दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी साझा किया कि वह पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात करने भी जाएंगे।इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्ष के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि छात्रों से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा कराई जाए। अपनी इस मुलाकात के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने का अनुरोध किया, जिस पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस संबंध में उन्हें पहले सरकार से बात करनी होगी।कांग्रेस नेता ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये युवा बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है और विपक्ष भी पूरी तरह उनके साथ है। राहुल गांधी ने मांग की कि प्रधानमंत्री को छात्रों पर पुलिस का बलप्रयोग बंद करवाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए।केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करते हुए राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर दोहराया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों को खुद शिक्षा मंत्री ने नहीं पीटा है, बल्कि इसके लिए गृह मंत्री के अधीन आने वाली पुलिस जिम्मेदार है, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने अंत में संकल्प दोहराया कि विपक्ष छात्रों से जुड़े इस अहम मुद्दे को संसद के भीतर लगातार उठाता रहेगा।

राज्यसभा में छात्रों के मुद्दे पर गरजे खरगे, बोले- चर्चा नहीं होने दी, सरकार ने हमारा मुंह बंद करा दिया

नई दिल्ली ((एजंसी) कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबा दी गई। उनका कहना था कि जैसे ही उन्होंने इस विषय पर बोलना शुरू किया, उनका माइक बंद कर दिया गया और चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित होने के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खरगे ने कहा कि विपक्ष राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और घायल छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहता था। साथ ही विपक्ष की मांग थी कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री सदन में बयान दें लेकिन सरकार ने इस पर चर्चा का अवसर नहीं दिया। खरगे ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और उन्हें क्यों पीटा गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया मेदान्ता हास्पिटल शिफ्ट करने का प्रस्ताव, जल्द आएगा विस्तृत आर्डर

नई दिल्ली ((एजंसी) दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने माना कि मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत थे कि उन्हें लगातार अस्पताल की निगरानी की जरूरत है, साथ ही सरकारी अस्पताल में रहने को लेकर उनके पत्र में जताई गई चिंताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने यह बात वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें वांगचुक को उनकी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं दी गई थी।कोर्ट के सामने रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करने और ।प्प्डै, सफदरजंग अस्पताल और वांगचुक का इलाज कर रही टीम के डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, बेंच ने पाया कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर आम सहमति थी कि उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रहना चाहिए। बेंच ने कहा कि हमारा सुझाव है कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल, मेदांता में शिफ्ट किया जाए। साथ ही, बेंच ने यह भी कहा कि वांगचुक ने अपने पत्र में जो चिंताएं जताई हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉ. आंग्मो की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिबल ने बताया कि वांगचुक के जरूरी मेडिकल पैरामीटर स्थिर हैं और भूख हड़ताल जारी रखते हुए भी वे ओरल रिहाइड्रेशन (मुंह से तरल पदार्थ) ले रहे हैं। उन्होंने वांगचुक के एक पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अस्पताल के अंदर उन पर पुलिस की निगरानी है और उन्हें अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।बेंच ने पूछा कि क्या वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने से ये चिंताएं दूर हो जाएंगी, जिस पर सिबल ने हामी भरी। सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या यूरिया और यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर किसी अंग के ठीक से काम न करने का संकेत है। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि लंबे समय तक भूखे रहने पर शरीर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के तौर पर फैट का

योगी कैबिनेट के 16 अहम फैसलों पर मुहर

विंध्य एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और 220 नई बसों को मंजूरी

लखनऊ, ((एजंसी) ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवहन, अग्निशमन सेवाओं और विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी। लगभग 333 किलोमीटर लंबे छह लेन (भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किए जाने योग्य) इस एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले जुड़ेंगे। परियोजना को 36 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी निर्माण लागत लगभग 18,514 करोड़ रुपये तथा भूमि अधिग्रहण पर 4,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल अनुमानित लागत करीब 26,315 करोड़ रुपये होगी। प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर से इसकी शुरुआत होगी।इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित करेगा। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड में विकासकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत वर्ष 2025–26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक महाविद्यालय की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, संबद्ध एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना आवश्यक होगा। स्कूटी का पंजीकरण शुल्क, बीमा और वितरण के समय पांच लीटर पेट्रोल का खर्च भी सरकार वहन करेगी। स्कूटी की खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनके लिए मेरिट की अनिवार्यता नहीं होगी।उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और पात्र महाविद्यालयों में शोधपीठ (चेयर) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिसे सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और उसके ब्याज से शोधपीठ का संचालन होगा। 50 वर्ष से अधिक पुराने तथा पांच हजार से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।कैबिनेट ने बसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए छात्रावास के निर्माण के लिए 248.30 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की।बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम को संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इस राशि की वापसी पांच वर्ष बाद शुरू होगी और दस वर्षों में दो–दो करोड़ रुपये की वार्षिक किश्तों में की जाएगी।परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 नई बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 50 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसें और 42 सीटों वाली अन्य बसें शामिल होंगी।अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के लिए नए वाटर टेंडर और फोम टेंडर वाहनों की खरीद एवं निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिससे विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत किया जा सकेगा।

सीजेपी प्रोटेस्ट पर अरविन्द केजरीवाल का एक्शन

डीसीपी को चिट्ठी लिख मांगी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की लिस्ट

नई दिल्ली जिले के DCP सचिन शर्मा को लिखे पत्र में केजरीवाल ने उन लोगों की जानकारी तुरंत जारी करने की मांग की, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जिन्हें विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मुझे पता चला है कि कल जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाबदेही की मांग कर रहे लोगों के खिलाफ कई थ्प्त दर्ज की गई हैं।

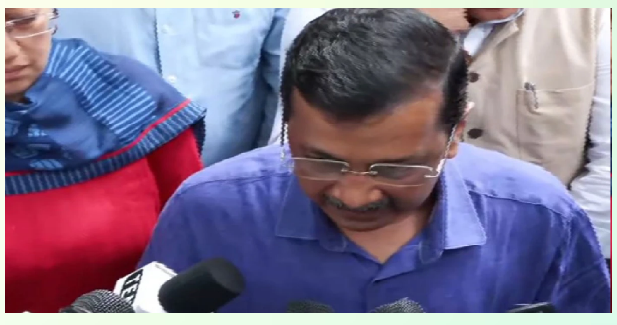

नई दिल्ली ((एजंसी) आम आदमी पार्टी (।।च) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्ब्च्) सचिन शर्मा को पत्र लिखकर सोमवार को जंतर–मंतर पर हुए ब्श्रच विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज थ्प्त और हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी मांगी। साथ ही, उन्होंने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया। नई दिल्ली जिले के क्ब्च् सचिन शर्मा को लिखे पत्र में केजरीवाल ने उन लोगों की जानकारी तुरंत जारी करने की मांग की, जिनके खिलाफ थ्प्त दर्ज की गई है और जिन्हें विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मुझे पता चला है कि कल जंतर–मंतर पर शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाबदेही की मांग कर रहे लोगों के खिलाफ कई थ्प्त दर्ज की गई हैं।उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह भी पता चला है कि कल के विरोध प्रदर्शन के बाद कई लोगों को बिना कोई थ्प्त दर्ज किए हिरासत में रखा गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि मेरी मांग है कि ऊपर बताई गई दोनों लिस्ट तुरंत सार्वजनिक की जाएं ताकि उन लोगों को उचित कानूनी मदद मिल सके। यह घटनाक्रम जंतर–मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद हुआ है, जहां कथित तौर पर पत्थरबाजी और गैर–कानूनी तरीके से जमा होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 5 थ्प्त दर्ज की हैं और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कथित हिंसा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक पांच एफआईआर दर्ज की हैं और इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हिंसा किसी पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (ठछै) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव (च्क्च्) एक्ट की अलग–अलग धाराओं के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में थ्प्त दर्ज की गई हैं।सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कथित हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 250 से ज्यादा वीडियो की जांच की है, जिनमें मोबाइल फोन क्लिप, ब्ब्ज्ट फुटेज, ड्रोन फुटेज और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज शामिल हैं। सोमवार को पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके में पत्थरबाजी का फुटेज जारी किया।

कोलकाता में ममता बनर्जी की बड़ी रैली

दिल्ली में बागी एनसीपीआई सांसदों ने किया शक्तिप्रदर्शन

शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए ज्डब् समर्थक कोलकाता में जमा हुए, और एक समर्थक ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताया। समर्थक ने कहा टीएमसी फिर जीतेगी। मैं दीदी का समर्थन करता हूं। इस बीच, शहीद दिवस पर कोलकाता में बोलते हुए ज्डब् सांसद सौगत रॉय ने 1993 की घटना को याद किया और बताया कि उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था।

नई दिल्ली ((एजंसी) तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बिड़ला तारामंडल में ईशहीद दिवसश रैली आयोजित की। यह रैली 1993 में लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की याद में की गई थी। शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए ज्डब् समर्थक कोलकाता में जमा हुए, और एक समर्थक ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताया। समर्थक ने कहा टीएमसी फिर जीतेगी। मैं दीदी का समर्थन करता हूं। इस बीच, शहीद दिवस पर कोलकाता में बोलते हुए ज्डब् सांसद सौगत रॉय ने 1993 की घटना को याद किया और बताया कि उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था।रॉय ने एएनआई को बताया उस समय, ममता बनर्जी के नेतृत्व में वोटर पहचान पत्र की मांग को लेकर निकाले जा रहे जुलूस पर कोलकाता में सरकारी पुलिस ने फायरिंग की थी। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। ममता बनर्जी तब से ही उस घटना की याद में शहीद दिवस मनाती आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शहीदों के लिए बहुत दुखी होने का दिखावा करती थीं, फिर भी उन्होंने मनीष गुप्ता को मंत्री बनाया। मनीष गुप्ता उस समय गृह विभाग के प्रधान सचिव थे और उन्हीं के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी। चुनाव हारने के बाद भी, उन्होंने उन्हें मंत्री से भी ऊंचा दर्जा दिया। घोष ने आरोप लगाया, सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने सुशांत चटर्जी आयोग की रिपोर्ट को सालों तक दबाए रखा और उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। आखिर, इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता को उनकी पार्टी में शामिल किया गया, मंत्री बनाया गया और यहां तक ध्धकि मंत्री से भी ऊंचा दर्जा दिया गया।इस बीच, छब्च् में शामिल हुए बागी ज्डब् सांसदों ने दिल्ली में राजघाट जाकर इस मौके को याद किया। बागी ज्डब् सांसद और छब्च् नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि वे 1993 में पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को याद करने के लिए राजघाट गए थे। बंद्योपाध्याय ने पत्रकारों से कहा कि 1993 में ज्योति बसु सरकार के समय पुलिस फायरिंग में यूथ कांग्रेस के 13 बेगुनाह कार्यकर्ता मारे गए थे।

अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडे की पांचवी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा

हरदोई। आज अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडे की पंचम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल श्री विष्णु कांत चतुर्वेदी जी के द्वारा की गई। सीतापुर रोड पर स्थित स्मारक स्थल पर मुख्य अतिथिके रूप में बोलते हुए श्री बृजेश कुमार पाठक जी ने अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडे को भारत माता का अमर सपूत बताया तथा उनके शौर्य एवं बलिदान को नमन किया। उन्होंने मेजर पंकज पांडे के माता–पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा ऐसे वीर सपूतों के माता–पिता आदर्श माता पिता होते हैं जो सभी के वंदनीय हैं। उन्होंने अपने भाषण में सी वी सैनिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता की चर्चा की। मेजर पंकज पांडे के पिताजी श्री अवध ेश पांडे जी के द्वारा दिए गए मांग पत्र के संदर्भ में उन्होंने हरदोई मेडिकल कॉलेज के नाम को अमर शहीद मेजर पंकज पांडे के नाम से करने का आश्वासन दिया अपने अध्यक्ष की उद्बोधन में लेफ्टिनेंट जनरल से विष्णु कांत चतुर्वेदी जी ने मेजर पंकज पांडे जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के त्याग और धैर्य के को नमन किया। उन्होंने भारतीय सेना के और सैनिकों के अनेक संस्मरण साझा करते हुए सैनिकों की श्रेष्ठ सेवाओं की चर्चा करते हुए उनकी पीड़ाओं को भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि का स्वागत अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडे जी के भाई आशीष पांडे द्वारा किया गया साथ ही साथी पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष कैप्टन श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष सूबेदार महेंद्र पाल सिंह तथा संयोजक भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ हरदोई के हवलदार पुष्पेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी जी का स्वागत श्री जयदीप कुमार मिश्रा अमर शहीद मेजर पंकज कुमार पांडे जी के बाल सखा तथा शीर्षेन्दु शीलत्रिवेदीके द्वारा किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉ सुशील चंद्र त्रिवेदी जी का स्वागत श्री वैभव त्रिपाठी तथा राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी का स्वागत श्री शोभित कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों के द्वारा पंकज कुमार पांडे जी के पिता श्री अवध ेश कुमार पांडे जी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्ताविकी डॉ पवन पुत्र बादल जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। संचालन डॉक्टर देश दीपक शुक्ल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती पीके वर्मा ,सदस्य विधान परिषद अवनीश कुमार सिंह माननीय विधायक सवाजपुर श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुखसागर मिश्रा मधुर ,कुशी बाजपेई,सुनील शुक्ला रानू अग्निहोत्री पारुल दीक्षित सहित तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिख बटालियन के जवान तथा पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे।

लखनऊ में होगा जूनियर मिस इंडिया सीजन 5 का भव्य आडिशन, बेटियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच'

'हर बेटी में है एक अनोखी पहचान... आइए, उसे दें राष्ट्रीय मंच और अपने सपनों को नई उड़ान'

लखनऊ। देश के सबसे प्रतिष्ठित गर्ल्स चाइल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एवं कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म 'जूनियर मिस इंडिया सीजन 5 का भव्य ऑडिशन इस रविवार, 26 जुलाई को वेव मॉल में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा' ।यह ऑडिशन लखनऊ की 5 से 16 वर्ष की सभी प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए खुला है। आयोजकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के इस मंच का लखनऊ में आयोजित होना गर्व की बात है ।जूनियर मिस इंडिया पिछले चार सफल सीजन से देशभर की हजारों बच्चियों को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखारने का अवसर प्रदान कर रहा है ।आयोजकों ने बताया कि जूनियर मिस इंडिया केवल एक फैशन या ब्यूटी पेजेंट नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ग्रूमिंग पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यहां प्रतिभागियों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बना सकें ।पिछले चार सीजन में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से हजारों प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिए, जिनमें से चयनित प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अनेक बच्चियों के लिए यह मंच उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। इस मंच ने उन्हें केवल मॉडलिंग या फैशन की दुनिया ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, बेहतर संवाद कौशल, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और नई पहचान भी दी है ।जूनियर मिस इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भारत के अलग–अलग राज्यों से आई बच्चियां एक साथ सीखती हैं, नई मित्रताएं बनाती हैं, विभिन्न संस्कृतियों को जानती हैं और एक–दूसरे से अनुभव साझा करती हैं। यह अनुभव उन्हें राष्ट्रीय एकता, सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना भी सिखाता है ।आयोजकों का कहना है कि हर बच्ची में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। आवश्यकता केवल सही मार्गदर्शन और सही मंच की होती है। जूनियर मिस इंडिया का उद्देश्य प्रत्येक बच्ची को ऐसा मंच देना है, जहां वह अपनी क्षमता को पहचान सके और अपने सपनों को नई उड़ान दे सके ।सीजन 5 को पिछले चार सफल सीजन के अनुभव, अभिभावकों के सुझाव और प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर और भी अधिक भव्य एवं प्रोफेशनल बनाया गया है। इस वर्ष प्रतिभागियों को उन्नत ग्रूमिंग सेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, रैंप ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फोटोशूट, फैशन शो, सेलिब्रिटी इंटरैक्शन

और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अनेक अवसर मिलेंगे ।आयोजकों ने लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को इस राष्ट्रीय मंच का हिस्साबनने का अवसर अवश्य दें। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने, व्यक्तित्व निखारने और जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणादायक यात्रा है ।ऑडिशन विवरणकार्यक्रमरू श्रनदपवत डपे प्दकपं˜मेंवद 5

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी ने भटनीहऔड़िहार रेलखंड का किया सेफ्टी आडिट, मानसून में सुरक्षित रेल संचालन पर जोर

वाराणसी, मानसून के दौरान सुरक्षित एवं सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करने और रेलखंड की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी नीरज गुप्ता ने बुधवार को मुख्यालय गोरखपुर से आई टीम के साथ वाराणसी मंडल के भटनीदृ औड़िहार रेलखंड का व्यापक सेफ्टी ऑडिट किया।

निरीक्षण के दौरान समपार फाटक, पुल–पुलिया, लिमिटेड हाइट सब–वे, ट्रैक, हाइट गेज, बूम लॉकिंग व्यवस्था, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर स्टिकर, सोलर लाइट, गेटमैन केबिन तथा गेटमैनों की दक्षता और मेडिकल प्रमाणपत्रों की गहन जांच की गई।

ऑडिट टीम ने भटनी, सलेमपुर, मऊ और औड़िहार स्टेशनों पर पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट्स, स्टेशन यार्ड, लॉन्ग वेल्डेड रेल सहित विभिन्न संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया। साथ ही इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं परिचालन विभाग के कर्मचारियों की दक्षता, सक्षमता प्रमाणपत्र और पीरियाडिकल मेडिकल परीक्षण अभिलेखों की भी समीक्षा की गई।

टीम ने भटनी रनिंग रूम का निरीक्षण कर गार्ड एवं लोको पायलटों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा ट्रैकमैन और लाइन कर्मचारियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं संरक्षा संबंधी जागरूकता का मूल्यांकन किया ।इसके अलावा बर्थिंग ट्रैक, पॉइंट मशीन, सिग्नलिंग प्रणाली, पैदल उपरिगामी पुल, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, अग्निशमन एवं अलार्म प्रणाली, रिले रूम और फेल–सेफ सिस्टम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। औड़िहार मेमू शेड एवं सैदपुर भीतरी लोको शेड का भी निरीक्षण किया गया, जहां ट्रैक एवं ट्रैक्शन लाइन फिटिंग्स की जांच की गई ।निरीक्षण के समापन पर अंतरमंडलीय सेफ्टी ऑडिट टीम ने सैदपुर भीतरी से बनारस तक सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल कर रेलखंड की संरक्षा एवं परिचालन व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यालय एवं वाराणसी मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर चिन्हित मकानों को लेकर बढ़ी चिंता, रवि चौधरी ने नवाबपुरा पहुंचकर लोगों को दिया भरोसा

'मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा'

मुरादाबाद। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नवाबपुरा से लेकर लालबाग क्षेत्र तक बड़ी संख्या में मकानों पर चिन्ह लगाकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने से स्थानीय निवासियों में चिंता और असमंजस का माहौल है। इसी विषय को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना ।इस दौरान महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी, जिला प्रमुख महासचिव गौरव कुमार, जिला सचिव फहद, जिला सचिव सलीम, महानगर सचिव ओसम, महानगर उपाध्यक्ष वीरपाल सैनी उर्फ मोनू सैनी, सूरज एवं रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे ।क्षेत्रवासियों ने रवि चौधरी को बताया कि नगर निगम द्वारा लगभग 800 से 1000 मकानों को चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में करीब 80 से 90 हजार लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से लोगों में अपने आशियाने को लेकर भय और चिंता व्याप्त है ।इस अवसर पर रवि चौधरी ने कहा कि किसी भी विकास कार्य का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशानी में डालना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन किसी योजना के अंतर्गत कार्रवाई करता है तो उससे पहले वहां रहने वाले लोगों की स्थिति, उनके अधिकारों और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ।रवि चौधरी ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा, ष्मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं। शासन और प्रशासन के समक्ष आपकी बात पूरी मजबूती से रखी जाएगी। किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर संभव प्रयास और मदद के लिए मैं सदैव आपके साथ हूं ।ष्उन्होंने आगे कहा कि नवाबपुरा क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश परिवार पीढ़ियों से वहीं निवास कर रहे हैं। उनके पास अपने मकानों के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज एवं पूर्वजों के निवास के प्रमाण उपलब्ध हैं, जिन्हें वे सरकार और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले संबंधित विभागों को इन सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण करना चाहिए। रवि चौधरी ने प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित किया जाए तथा ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और वर्षों से बसे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। मुरादाबाद से पवन गुप्ता की रिपोर्ट

'आज जनसेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खान के नेतत्व में'

'मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा'

रामपुरः उत्तर प्रदेशःरामपुरःजन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खा ने बोलते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी हमारे देश का भविष्य है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी इमारत रेता बजरी ईट जौहर यूनिवर्सिटी नहीं इसमें पढ़ने वाले बच्चे और इसको बनाने में इसको संवारने में और जो बच्चे यहां से डिग्री लेकर निकलेंगे उसको जौहर यूनिवर्सिटी कहते हैं छात्र–छात्राएं शिक्षा हासिल करने के लिए रामपुर और बाहर शहरों से पढ़ने आते हैं जिनको एक साल 2 साल 3 साल हो चुके शिक्षा हासिल करते हुए और इस टाइम न्यू एडमिशन भी हो रहे हैं इन छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को चाहिए की की छात्र–छात्राओं की पढ़ाई भी खराब ना हो जौहर यूनिवर्सिटी 38भवन को आरडीए आवेद घोषित करा है और 15दिन का तोड़ने का आर्डर किया है हम प्रदेश सरकार से अपील करते इस आदेश को वापस लेना चाहिए और कंपाउंड लगाकर उसका नक्शा पास करना चाहिए जबकि यह यूनिवर्सिटी 20 साल पहले बनी थी और उसे टाइम वहां पर आरडीए नहीं था वसीम उल हसन खान हारिस शमसी ऋषभ शर्मा शिबू खान मनी सिंह वसी खान शिराज शमसी फैजान खान अंकित अग्रवाल याहया शमसी अशोक कुमार सैनी आदि मौजूद थे

'चिराग इंटरनेशनल क्लब के सौजन्य से वृक्षारोपण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।'

'मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा'

रामपुरः उत्तर प्रदेशःरामपुर ।में इंटरनेशनल क्लब की ओर से कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था और सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र शील्ड एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रकृति, पर्यावरण, स्वच्छता एवं सामाजिक विषयों पर सुंदर चित्र प्रस्तुत किए। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्लब की संस्थापक सरिता विश्नोई , उपाध्यक्ष यामिनी गुप्ता , पारूल बंसल एवं लता भाटिया जी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या शारदा नरूला जी का सम्मान किया गया ।सभी उपस्थित बहनों एवं अतिथियों ने समय पर पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। यह आयोजन बच्चों के लिए प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक रहा तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को सकारात्मक संदेश देने में सफल सिद्ध हुआ।

मुख्य विकास अधिकारी का उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया सम्मान, कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया आश्वासन

वाराणसी। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, शाखा वाराणसी के पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह (आईएएस) एवं जिला विकास अधिकारी विजय कुमार जायसवाल का शॉल, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।

इस अवसर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, कार्यवाहक अध्यक्ष रामबदन यादव तथा उपाध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया।

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने महासंघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी को कोई भी समस्या हो तो वह सीधे उनसे संपर्क करे। कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

महासंघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी का कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

वित्तीय साक्षरता शिविर संपन्न लखनऊ 21 जुलाई ब्लॉक चिनहट अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर में क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा एक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को केसीसी प्रध ाानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सुकन्या समृद्धि योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना अटल पेंशन योजना साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी गई इस अवसर पर असिस्टेंट एल डीएम लखनऊ गन्ना अधिकारी लखनऊ बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया सी बी ओ विजय वर्मा फील्ड कोऑर्डिनेटर चिनहट राकेश गुप्ता सहित कई दर्जन ग्रामीण उपस्थित रहे

छात्रों के बीच राहुल की मौजूदगी से सत्ता दल की बेचौनी बढ़ी, अशोक विश्वकर्मा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश ओबीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा है कि राहुल गांध ी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से लगातार छात्रों के बीच जाकर उनके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए वो ना तो किसी दल विशेष तथा किसी व्यक्ति विशेष को बुरा भला कहते हैं। छात्रों के साथ उनका संबोधन पूरी तरह गैर–राजनीतिक है। छात्रों के बीच राहुल की मौजूदगी ने सत्ताध ारी दल और उसके 'थिंक टैंक' की बेचौनी बढा दी है। राहुल के नेतृत्व में लामबंद होती आवाजों को रोकने के लिए 'जंतर–मंतर' पर हंगर स्ट्राइक किया गया और देश भर के छात्रों का आह्वान किया गया। ताकि राहुल जैसा व्यक्ति विपक्ष की आवाज ना बन सके। मौजूदा सरकार का चरित्र यही रहा है, कि वो विपक्ष भी अपनी मर्जी का चाहती है। इस सरकार को राहुल विपक्ष में भी बर्दाश्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निष्क्रिय साबित करने के लिए, 'जंतर–मंतर' का आंदोलन रचा गया। लेकिन अब स्थिती बदल गई है। दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में भी युवा आंदोलनरत हो सकते हैं, इसकी उम्मीद 'जंतर–मंतर' रचने वालो को भी नहीं रही होगी। युवाओं का यह आंदोलन 'जंतर–मंतर' रचने वालो के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल का एजेंडा भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अब इन युवाओं को नेतृत्व की जरूरत है। वो नेतृत्व ना तो सोनम वांगचुक में नजर आता है और ना ही 'कॉकरोचों में! अब सवाल है कि वह नेतृत्व कौन करेगा? घूम फिरकर सबकी निगाहें एक ही शख्स पर जाकर रुक जाती हैं और वह शख्स राहुल गांधी है!

देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार

मिर्जापुर 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लोक सभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार और छात्रों युवाओं पर बर्बारता लाठियों से पीटे जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना था जिसमें सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के गलत नीतियों के कारण पर छात्र एवं युवाओ के तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का इकलौता सहारा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है श्री चौधरी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरा सिस्टम अडानी–अंबानी के हाथों में सौंप दिया गया है

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने कहा कि

बीजेपी सरकार में छात्र आज निराश होकर कह रहे हैं कि इस देश में उनका कोई भविष्य नहीं बचा। इस नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान को डांकिगज निवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया मिन्हाज अहमद छोटे खान ने कहा कि छात्रों के मुद्दा को लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर शांतिपूर्ण मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी एवं सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय है श्री खान ने कहा कि

लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना अपराध नहीं है। छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय विपक्ष की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है

श्री खान ने कहा कि जननायक राहुल गांधी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ हुए इस शर्मनाक व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ । देश के युवाओं की आवाज को न तो डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। हम छात्रों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगे

उपस्थित जिला पंचायत सदस्य शिव शंकर चौबे शशि भूषण दुबे रमेश प्रजापति पप्पू दुर्गा प्रसाद चौधरी जिला पंचायत सदस्य कृष्ण गोपाल चौधरी राजधर दुबे राजेंद्र विश्वकर्मा आनंद त्रिपाठी मृत्युंजय मिश्रा अंकुर श्रीवास्तव आजाद संतोष यादव इश्तियाक अंसारी राजेश मिश्रा ज्योति विजय दुबे पहाड़ी रामनाथ दुबे रितेश मिश्रा डॉक्टर दिनेश चौधरी कुंज बिहारी उपाध्याय शिव शंकर पांडे अशोक गुप्ता जैकी कोल डिंपू यादव

बोधी पथ कार्यशाला का समापन, कुलपति व विधायक ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ

मिर्जापुर। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं के.बी. पी.जी. कॉलेज, मिर्जापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय 'बोधी पथ' कार्यशाला का समापन समारोह शनिवार को के.बी. पी.जी. कॉलेज सभागार में संपन्न हुआ।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. शोभा गौड़ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा उपस्थित रहे।

कुलपति प्रो. शोभा गौड़ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा की उपयोगिता पर बल देते हुए छात्रों व शिक्षकों को "एक व्यक्ति–एक पौधा" का प्रण कराया। उन्होंने कहा, "प्रकृति का दोहन न करें, उसका पालन–पोषण करें। प्रकृति है तभी जीवन है, इसलिए अपना जीवन प्रकृति संरक्षण में समर्पित करें।"

विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में सतत विकास, भारतीय दर्शन एवं 'भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं। पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पर्यावरण संतुलन के लिए किस तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मंच पर रही गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के वरिष्ठतम सदस्य पंडित तरुणेश मिश्रा तथा अगरतला स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के बौद्ध दर्शन के आचार्य प्रो. अवधेश कुमार चौबे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे।

इनके अलावा बिनानी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. अशोक कुमार सिंह, मां विंध्यवासिनी स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. संजीव कुमार सिंह, प्रो. भवभूति मिश्रा एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पधारे डॉ. राहुल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

समारोह में डॉ. कुलदीप पाण्डेय की नव प्रकाशित पुस्तक 'सामाजिक समरसता के संवाहक – संत समाज' का मंच से लोकार्पण कुलपति व विधायक द्वारा किया गया।

कार्यशाला में पंजीकृत सभी छात्रों एवं शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉ. कुलदीप पाण्डेय ने किया।

इस अवसर पर प्रो. अर्चना पांडे, प्रो. नम्रता मिश्रा, प्रो. भानु प्रताप सिंह, प्रो. जी.एस. द्विवेदी, प्रो. देवेंद्र पाण्डेय, डॉ. रविन्द्र प्रताप सिंह, डॉ. राजमणि सरोज समेत बड़ी संख्या में शिक्षकगण व छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

शिवभूषण त्रिपाठी निर्विरोध बने प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष

रिपोर्ट सुनील पाण्डेय

रामनगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रामनगर ब्लॉक इकाई का चुनाव बुधवार को बीआरसी रामनगर के सभागार में निर्विरोध संपन्न हुआ। सभी पदों पर एकल नामांकन होने के कारण पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।जिला कार्यसमिति की ओर से नामित निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार शुक्ला और पर्यवेक्षक जिला मंत्री नारायण सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें शिवभूषण त्रिपाठी को ब्लॉक अध्यक्ष, सतीश सिंह को ब्लॉक मंत्री और मनीष कुमार तिवारी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। मनीष द्विवेदी संगठन मंत्री निर्वाचित हुए।ब्लॉक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर दिनेश सिंह और मंत्री पद पर सचिन मिश्र निर्वाचित हुए। वहीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना देवी निर्विरोधा चुनी गईं।मुख्य अतिथि प्रांतीय संगठन मंत्री एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने पदाधिकारियों से निष्पक्षता और निष्ठा के साथ शिक्षक हित में कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही शिक्षकों से एकजुट रहकर समस्याओं और दुर्व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करने की बात कही।इस दौरान संदीप शुक्ला, ब्रजेश कुमार, हरिशंकर तिवारी, आराधना सिंह, गंगा शुक्ला, अमित पांडेय, रामभूषण, विजय शुक्ला और देवकुमार यादव समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

इनर व्हील क्लब वाराणसी 'मित्रम' की अध्यक्ष बनीं डश शालिनी सिंह, पदग्रहण समारोह में हुए कई सेवा प्रकल्प

रोटी बैंक को खाद्य सामग्री, विद्यार्थियों को स्टेशनरी और पॉलीथिन मुक्त भारत के लिए जूट के थैले वितरित

वाराणसी। इनर व्हील क्लब वाराणसी 'मित्रम' का पदग्रहण समारोह ककरमत्ता स्थित ली लोटस होटल में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरार डॉ अनुराधा भाटिया तथा क्लब की संस्थापिका पीएटीध्पीडीसी डॉ अंजलि अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया।इस अवसर पर सत्र 2026–27 के लिए नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नई टीम में डॉ शालिनी सिंह ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा सतरूपा को वाइस प्रेसीडेंट, वंदना श्रीवास्तव को सचिव, डॉ ममता तिवारी को कोषाध्यक्ष, गीता अग्रवाल को आईएसओ तथा डॉ सरोज राय को एडिटर नियुक्त किया गया।

अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ शालिनी सिंह ने सेवा, सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्लब की गतिविधियों को और विस्तार देने का संकल्प व्यक्त किया।

समारोह के दौरान विभिन्न सामाजिक प्रकल्प भी संचालित किए गए। रोटी बैंक को खाद्य सामग्री प्रदान की गई, विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई तथा पॉलीथिन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जूट के थैले और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे वितरित किए गए।कार्यक्रम में श्रेयसी मिश्रा ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। समारोह का संचालन डॉ अंजलि अग्रवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सतरूपा ने दिया। इस अवसर पर निशा,श्वेता, शाइस्ता, आशा अग्रवाल, मंजू केशरी, उमा केशरी सहित क्लब की अनेक सदस्याएं उपस्थित रहीं।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, को ध्वस्त किए जाने के आदेश के विरोध में A का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

संवाददाता

प्रयागराज में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (।प्डप्ड) के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर को ध्वस्त किए जाने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अफसर महमूद के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।ज्ञापन में मांग की गई कि विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत समीक्षा कराई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में कानून के दायरे में रहकर निर्णय लिया जाना चाहिए और किसी भी कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन होना चाहिए।प्रदर्शन के दौरान ।प्डप्ड कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और प्रशासन से ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाने का अनुरोध किया।यह मामला न्यायालय के आदेश, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया से जुड़ा है। प्रदर्शन के माध्यम से ।प्डप्ड ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय को लेकर अंतिम स्थिति न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी। इस मामले से जुड़े आधिकारिक तथ्यों और आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है।

मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में पहली बार च्त्च थेरेपी से बाल उगाने की प्रक्रिया सफल, अब बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा

मिर्जापुररूमां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां के त्वचा एवं यौन रोग विभाग में बालों की वृद्धि के लिए पहली बार पीआरपी (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा) थेरेपी सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

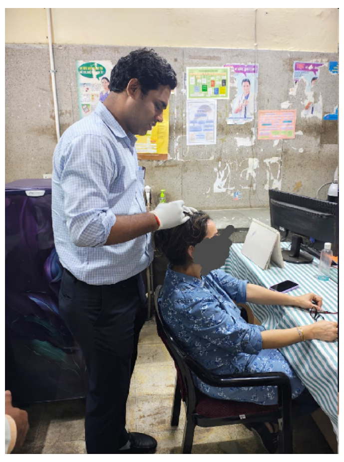

अब मिर्जापुर में ही मिलेगा एडवांस हेयर रिस्टोरेशन, इस आधुनिक उपचार के शुरू होने से मिर्जापुर समेत सोनभद्र, भदोही, चंदौली व प्रयागराज के मरीजों को बाल झड़ने व गंजेपन के इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।स्थानीय स्तर पर ही विश्वस्तरीय हेयर रिस्टोरेशन की सुविधा मिलेगी।

यह थेरेपी त्वचा एवं यौन रोग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रणव सत्यराज के नेतृत्व में सफलतापूर्वक की गई। डॉ. सत्यराज ने बताया कि च्त्च एक आधुनिक व न्यूनतम हस्तक्षेप वाली प्रक्रिया है। इसमें मरीज के खून से प्लेटलेट्स युक्त प्लाज्मा निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह इलाज चिकित्सकीय जांच व परामर्श के बाद चुनिंदा मरीजों पर किया जाता है। बेहतर रिजल्ट के लिए कई सत्र लग सकते हैं और जरूरत पर अन्य दवाओं के साथ भी इसे किया जाता है।

सीएमएस डॉ. सचिन किशोर ने कहा कि इस सुविधा से मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. संजीव कुमार सिंह ने इसे कॉलेज की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, ऋ"हमारा लक्ष्य आधुनिक, वैज्ञानिक व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक पहुंचाना है। त्वचा रोग विभाग भविष्य में भी स्किन व बालों से जुड़े एडवांस इलाज मिर्जापुर में उपलब्ध कराता रहेगा, ताकि मरीजों को सस्ता व सुलभ इलाज मिल सके।

बारा विधानसभा की जनता के प्यार और दुलार का मैं ऋणी हूं : विधायक डा. वाचस्पति

प्रयागराज। बारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. वाचस्पति ने मंगलवार को अपना 70वां जन्मदिन समर्थकों, मतदाताओं और क्षेत्रवासियों के बीच उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों, अस्पतालों, विकास खंड कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने के लिए लगभग 100 वाटर कूलर जनहित में वितरित किए।गौहनिया स्थित एमवी कॉन्वेंट स्कूल परिसर में विधायक डॉ. वाचस्पति के जन्मदिन एवं एमवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्थापना दिवस का संयुक्त रूप से भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। ढोल–नगाड़ों की गूंज और बिरहा गायकों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को उत्सव का स्वरूप प्रदान किया।शुभकामनाओं और स्वागत से अभिभूत विधायक डॉ. वाचस्पति ने कहा, ष्बारा विधानसभा की जनता ने मुझे हमेशा प्यार, सम्मान और स्नेह दिया है। मैं इस स्नेह और विश्वास का सदैव ऋणी रहूंगा तथा जनसेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा।

जनहित में भेंट किए 100 वाटर कूलरअपने जन्मदिन को जनसेवा से जोड़ते हुए विधायक डॉ. वाचस्पति ने क्षेत्र के निजी अस्पतालों, विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों को वाटर कूलर भेंट किए। उन्होंने कहा कि समाज सेवा और जनकल्याण ही उनके सार्वजनिक जीवन का उद्देश्य है तथा भविष्य में भी क्षेत्र की जनता के हित में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे।कार्यक्रम के अंत में विधायक का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर दीर्घायु, स्वस्थ एवं सफल जीवन की शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख इन्द्रनाथ मिश्रा, अजीत सिंह श्पप्पूश, खंड विकास अधिकारी जसरा एवं कौंधियारा, अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष राम मनोहर पटेल, पूर्व मंत्री बाबूलाल भंवरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मीडियाकर्मियों ने भी दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

विधायक डॉ. वाचस्पति को वरिष्ठ पत्रकारों एवं समाजसेवियों ने भी पुष्पगुच्छ एवं गुलाब भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरकार, परवेज आलम, वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि श्यामू निषाद, इसरार अहमद, अशफाक अहमद श्बाबा टंकीश, कल्लन राम मांझी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

पीएमएफएमई योजना से दो लाख सूक्ष्म उद्यमियों को मिला नया अवसर चिराग पासवान

वाराणसीध्नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (च्ड्थ्डम्) योजना के तहत ऋण से जुड़ी दो लाख से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस योजना ने छोटे उद्यमियों को वित्त, तकनीक और बाजार से जोड़कर उन्हें रोजगार सृजक बनने का अवसर दिया है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 44 प्रतिशत लाभ महिला उद्यमियों को मिला है, जबकि चार लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भी लाभान्वित हुए हैं। अब तक 20,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है और करीब छह लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल ऋण स्वीकृत करना नहीं, बल्कि हर उद्यम को सफल व्यवसाय में बदलने में निरंतर सहयोग देना है, ताकि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिले।

12 जुलाई से शुरू हुआ है बालाजी डे क्रिकेट टूर्नामेंट, विजेता टीम को मिलेगा 51 हजार का पुरस्कार

वाराणसी। नाटी इमली स्थित भारत मिलाप मैदान में 12 जुलाई से बालाजी डे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी और रोमांचक मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। टूर्नामेंट की विजेता टीम को घ51,000 तथा उपविजेता टीम को घ25,000 की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को श्मैन ऑफ द सीरीजश के रूप में साइकिल पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।

टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक एवं मुख्य अतिथि दिव्यांशु सेठ होंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक खेल प्रेमियों से प्रतियोगिता का आनंद लेने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

भारत में खो गई है जवाबदेही?

श्रुति व्यास

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए पहली बार लगा कि भारत में केवल राजनीति नहीं बदली है, जवाबदेही भी बदल गई है।

1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव खारिज किया था। फैसला सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लगाया। वह लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। आरोप प्रधानमंत्री पर था और पूरा देश जानता था कि जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। सत्ता बचाने का उनका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन जवाबदेही का अंतिम पता किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। भारत का हर नागरिक जानता–समझता था

चौदह वर्ष बाद यही कसौटी राजीव गांधी के सामने आई। वे ष्मिस्टर क्लीनष् की छवि लेकर सत्ता में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद उनकी पूरी राजनीतिक पहचान पर छा गया। हालांकि अदालत कभी यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली थी। फिर भी जनता ने राजनीतिक फैसला दे दिया। प्रधानमंत्री के इतने निकट हुआ सौदा प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी भी बना। और1989 में उसकी कीमत उन्हें सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी।

फिर मनमोहन सिंह आए। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, पद की जवाबदेही भी तय करता है। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवाद उनके कार्यकाल में सामने आए। लंबे समय तक कोयला मंत्रालय स्वयं उनके पास था। इसलिए ष्मुझे जानकारी नहीं थीष् जैसी सफाई राजनीतिक रूप से टिक नहीं सकी। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपनी जेब भरी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुँच चुका था। 2014 में उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस ने चुकाई।

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंहकृतीनोंएक–दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी उनमें एक समानता थी। उनके आसपास पैदा हुआ बड़ा विवाद अंततरू प्रधानमंत्री तक पहुँचता था। कभी प्रतिष्ठा जाती थी, कभी सरकार, कभी दोनों। उस समय जवाबदेही को सत्ता के शिखर (प्रधानमंत्री पद) तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगता था।

यही भारतीय लोकतंत्र का विकास था। उपलब्धि थी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आदत थी। लोकतंत्र में सरकार का चेहरा ही उसकी अंतिम जवाबदेही भी होता था।यहीं मुझे लगता है कि पिछले दशक में सबसे बड़ा बदलाव आया है।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का दशक विवादों से खाली नहीं रहा। किसानों का लंबा आंदोलन हुआ। देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सांसद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार–बार लीक हुए। भर्ती प्रक्रियाएँ संदेह के घेरे में आईं। लद्दाख में असंतोष बना। कई मौकों पर नागरिकों ने सरकार से जवाब माँगा।लेकिन इन सबमें एक बात समान रही। विवाद जंतर–मंतर, दिल्ली के प्रवेश दरवाजों तक और सरकार तक भी पहुँचे, मगर प्रधानमंत्री तक नहीं।

यही इस दौर की सबसे असाधारण राजनीतिक विशेषता है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध करने वाले वही वर्ग थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। अच्छे दिनों के वायदे में किसान राष्ट्र की रीढ़ बताए गए थे। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। ष्डेमोग्राफिक डिविडेंडष् केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल की राजनीतिक कथा थी।

2018 में तुमकुरु के एक युवा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि समाज के लिए ष्विद्यार्थी देवो भवष् मंत्र है, तो उनके लिए ष्युवा शक्ति देवो भवष् मंत्र है।फिर प्रश्नपत्र लीक का दौर आया। करोड़ों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईंय उन्होंने व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोया। स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिसने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया, वही उनके सबसे कठिन समय में सबसे पहले दिखाई देगा।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ।पहले सन्नाटा रहा। फिर प्रतीक्षा। फिर वही मंत्री अपने पद पर बने रहे जिनके विभाग पर सवाल उठ रहे थे। धीरे–धीरे शिकायत से अधिक चर्चा शिकायत करने वालों पर होने लगी। भारतीय राजनीति मेंयह नई रणनीति नहीं है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कठिन हो, तो बहस को प्रश्न से हटाकर विरोध पर ले जाइए। धीरे–धीरे मूल प्रश्न ही धुँधला पड़ जाता है।

यही बात दूसरे विवादों मेंभी दिखाई देती है।ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की सात शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लंबे समय तक पद पर बने रहे। राष्ट्रीय परीक्षा विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठे। हर बार राजनीतिक बहस किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी संस्था तक पहुँची, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक पहुँची।पहले ऐसा नहीं होता था।

इनमें से हर विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय के इतना निकट था कि भारतीय राजनीति के पहले के दौर में वह एक–दो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ता। अब वह जैसे अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने से पहले ही रुक जाता है।

ऐसा क्यों?

इसका एक उत्तर राजनीतिक प्रबंधन में है। हर सरकार विवादों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जाँच बैठती है, समय लिया जाता है, बहस का केंद्र बदला जाता है। मोदी सरकार ने यह कला असाधारण दक्षता से सीखी है। लेकिन केवल राजनीतिक प्रबंधन पर्याप्त उत्तर नहीं है।उसके लिए नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि को भी समझना होगा। उनके पीछे कोई राजनीतिक वंश नहीं है। रिश्तेदारों के लाभ उठाने की सार्वजनिक कहानियाँ नहीं हैं। निजी संपत्ति बढ़ाने की व्यापक धारणा भी नहीं है। उन्होंने स्वयं को बार–बार ष्फकीरष् कहा है। बड़ी संख्या में लोग इस छवि पर विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास केवल नेता की छवि नहीं बदलता, जवाबदेही का रास्ता भी बदल देता है।फिर भी यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है।

यदि प्रधानमंत्री वास्तव में अपने आसपास के विवादों से पूरी तरह अछूते हैं तो फिर वही विवाद बार–बार बने क्यों रहते हैं? जो नेता व्यक्तिगत रूप से सबसे सुरक्षित हो, उसके लिए विवादित सहयोगियों से दूरी बनाना, उन्हे हटाना सबसे आसान होना चाहिए। वास्तविक अधिकार वही है जो अपने लोगों पर भी लागू हो सके।लेकिन बार–बार उलटा दिखाई देता है। विवाद समाप्त करने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलने का निर्णय लिया जाता है।संभव है इसका उत्तर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत निष्कलंकता से कम और उनकी तथा अमित शाह की राजनीतिक गणित से अधिक जुड़ा हो। हर नेता निष्ठाओं के नेटवर्क के सहारे शासन करता है। किसी प्रभावशाली सहयोगी को हटाना केवल नैतिक निर्णय नहीं, राजनीतिक जोखिम भी है। शक्ति–संतुलन बदलता है, संगठन को संदेश जाता है और समीकरण प्रभावित होते हैं। इसलिए विवाद को सह लेना, कई बार उसे समाप्त करने से सस्ता पड़ता है।

या फिर बात इससे भी आगे की है।संभव है नेतृत्व को अब यह भरोसा हो गया हो कि विवाद, आंदोलन, असंतोष, गुस्सा शीर्ष नेतृत्व तक राजनीतिक नुकसान पहुँचाने की क्षमता खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के बीच बना भावनात्मक संबंध इतना मजबूत हो चुका है कि बड़ी संख्या में मतदाता प्रधानमंत्री और उनके नाम पर शासन करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर कर लेते हैं। सरकार से शिकायत हो सकती है, किसी मंत्री से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी स्वतरू प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचती।

यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है जो शायद नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है।

लोकतंत्र का तब क्या होता है, जब जवाबदेही अपनी पूरी यात्रा करना बंद कर दे?स्वतंत्र भारत के अधिकांश इतिहास मेंराजनीतिक जिम्मेदारी अंततरू सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुँच जाती थी। कभी वह प्रक्रिया अपूर्ण थी, कभी कठोर, कभी अन्यायपूर्ण भी। लेकिन यात्रा पूरी होती थी।आज असहमति अब भी है। आंदोलन भी हैं। सवाल भी हैं। बदला है तो केवल उनका रास्ता।

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसने मुझे इसी बदलाव का एहसास कराया। प्रश्न उठा, लेकिन वह भी अंततरू उसी जगह जाकर ठहर गया जहाँ पिछले कई वर्षों से दूसरे प्रश्न ठहरते आए हैं।शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। भारत में विवाद खत्म नहीं हुए हैं। विरोध भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जवाबदेही जैसे अपनी आखिरी सीढ़ी तक पहुँचना भूल गई है।यह केवल एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक मनोविज्ञान की कहानी है

सम्पादकीय

भारत में खो गई है जवाबदेही?

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए पहली बार लगा कि भारत में केवल राजनीति नहीं बदली है, जवाबदेही भी बदल गई है।1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव खारिज किया था। फैसला सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लगाया। वह लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। आरोप प्रधानमंत्री पर था और पूरा देश जानता था कि जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। सत्ता बचाने का उनका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन जवाबदेही का अंतिम पता किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। भारत का हर नागरिक जानता–समझता था

चौदह वर्ष बाद यही कसौटी राजीव गांधी के सामने आई। वे ष्मिस्टर क्लीनष् की छवि लेकर सत्ता में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद उनकी पूरी राजनीतिक पहचान पर छा गया। हालांकि अदालत कभी यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली थी। फिर भी जनता ने राजनीतिक फैसला दे दिया। प्रधानमंत्री के इतने निकट हुआ सौदा प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी भी बना। और1989 में उसकी कीमत उन्हें सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी।

फिर मनमोहन सिंह आए। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, पद की जवाबदेही भी तय करता है। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवाद उनके कार्यकाल में सामने आए। लंबे समय तक कोयला मंत्रालय स्वयं उनके पास था। इसलिए ष्मुझे जानकारी नहीं थीष् जैसी सफाई राजनीतिक रूप से टिक नहीं सकी। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपनी जेब भरी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुँच चुका था। 2014 में उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस ने चुकाई।इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंहकृतीनों एक–दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी उनमें एक समानता थी। उनके आसपास पैदा हुआ बड़ा विवाद अंततरू प्रधानमंत्री तक पहुँचता था। कभी प्रतिष्ठा जाती थी, कभी सरकार, कभी दोनों। उस समय जवाबदेही को सत्ता के शिखर (प्रधानमंत्री पद) तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगता था।यही भारतीय लोकतंत्र का विकास था। उपलब्धि थी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आदत थी। लोकतंत्र में सरकार का चेहरा ही उसकी अंतिम जवाबदेही भी होता था।यहीं मुझे लगता है कि पिछले दशक में सबसे बड़ा बदलाव आया है।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का दशक विवादों से खाली नहीं रहा। किसानों का लंबा आंदोलन हुआ। देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सांसद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार–बार लीक हुए। भर्ती प्रक्रियाएँ संदेह के घेरे में आईं। लद्दाख में असंतोष बना। कई मौकों पर नागरिकों ने सरकार से जवाब माँगा।लेकिन इन सबमें एक बात समान रही। विवाद जंतर–मंतर, दिल्ली के प्रवेश दरवाजों तक और सरकार तक भी पहुँचे, मगर प्रधानमंत्री तक नहीं।यही इस दौर की सबसे असाधारण राजनीतिक विशेषता है।यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध करने वाले वही वर्ग थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। अच्छे दिनों के वायदे में किसान राष्ट्र की रीढ़ बताए गए थे। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। ष्डेमोग्राफिक डिविडेंडष् केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल की राजनीतिक कथा थी।2018 में तुमकुरु के एक युवा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि समाज के लिए ष्विद्यार्थी देवो भवष् मंत्र है, तो उनके लिए ष्युवा शक्ति देवो भवष् मंत्र है।फिर प्रश्नपत्र लीक का दौर आया। करोड़ों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईंय उन्होंने व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोया। स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिसने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया, वही उनके सबसे कठिन समय में सबसे पहले दिखाई देगा।लेकिन ऐसा नहीं हुआ।पहले सन्नाटा रहा। फिर प्रतीक्षा। फिर वही मंत्री अपने पद पर बने रहे जिनके विभाग पर सवाल उठ रहे थे। धीरे–धीरे शिकायत से अधिक चर्चा शिकायत करने वालों पर होने लगी। भारतीय राजनीति में यह नई रणनीति नहीं है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कठिन हो, तो बहस को प्रश्न से हटाकर विरोध पर ले जाइए। धीरे–धीरे मूल प्रश्न ही धुँधला पड़ जाता है।यही बात दूसरे विवादों में भी दिखाई देती है।ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की सात शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लंबे समय तक पद पर बने रहे। राष्ट्रीय परीक्षा विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठे। हर बार राजनीतिक बहस किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी संस्था तक पहुँची, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक पहुँची।पहले ऐसा नहीं होता था।

इनमें से हर विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय के इतना निकट था कि भारतीय राजनीति के पहले के दौर में वह एक–दो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ता। अब वह जैसे अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने से पहले ही रुक जाता है।ऐसा क्यों?

क्या हैं सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के मायने

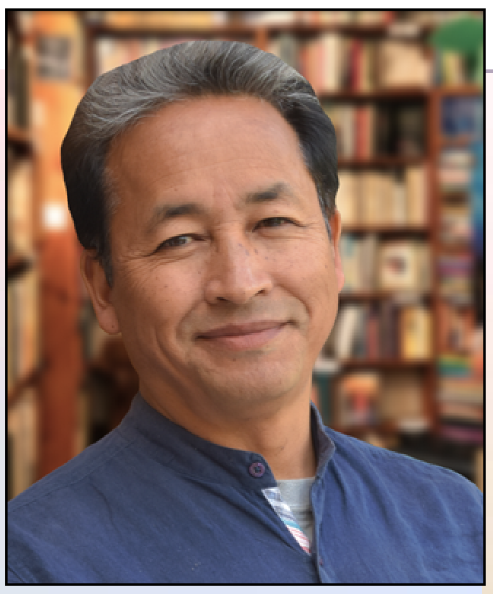

1. आमरण अनशन एक अहिंसक नैतिक अस्त्र–आमरण अनशन, विरोध, नैतिक आग्रह और लोकतंत्र एक शक्तिशाली अस्त्र है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां यह केवल एक भूख हड़ताल ही नहीं अपितु सरकार से अपनी बात मनवाने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सत्ता या समाज के विवेक को जगाने तथा उनकी आत्मा को झकझोरने के लिए एक अत्यन्त शक्तिशाली और अहिंसक नैतिक अस्त्र साबित हुआ है।

2. इतिहास में दर्ज कहानियां–भारतीय संस्कृति में आमरण अनशन की एक ऐतिहासिक गौरवशाली परम्परा रही है। ऋषियों–मुनियों द्वारा प्रायश्चित या अपनी मांगों के लिए उपवास का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है। स्वाधीनता संग्राम के समय ब्रिटिश साम्राज्य को अपना विरोध जताने एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए महात्मा गांधी ने इसे वैश्विक मंच दिया। उन्होंने देश को आजाद कराने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरोध में अनेक बार आमरण अनशन किये और ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आधुनिक समय में अन्ना हजारे के आन्दोलन को अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, जब हमने देखा था कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लोकपाल बिल की नैतिक मांग के आगे सरकार घुटनों पर आ गई थी और पूरा देश उनके समर्थन में आ गया था।

3. अनशन की ताकत–महात्मा गांधी ने कहा था आमरण अनशन विरोध का अन्तिम उपाय होना चाहियें इससे पहले सभी शान्तिपूर्ण संवाद के मार्ग अपनाए जाने चाहिये। क्योंकि यह मात्र भूख हड़ताल नहीं है अनशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक ऐसी तपस्या है जो कि सामाजिक कल्याण के खास उद्देश्य को प्राप्त करना है तथा सत्ता को एक नैतिक संदेश देना है।

4. क्यों है वांगचुक का अनशन–वर्तमान समय में सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् शिक्षाविद् सोनम वांगचुक 28 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित कालीन आमरण अनशन पर हैं। उनके उपवास को बीस दिन से ऊपर हो चुके हैं। वे विगत माह विशेषकर नीट यूपी 2026 में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ देश भर के बच्चों के द्वारा किये जा रहे आंदोलन में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

5. आन्दोलन के उद्देश्य–आरम्भ में यह आंदोलन मुख्य रूप से हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शुरू किया था। शुरू में यह आंदोलन सिर्फ बच्चों के विरोध के रूप में दिखाई दे रहा था, बाद में वांगचुक और अखिल भारतीय छात्र संघ के सम्मिलित होने से एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप परिवर्तित हो गया। सोनम वांगचुक द्वारा धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उनका वजन लगातार कम हो रहा है जोकि चिन्ताजनक है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि आगे आने वाला समय उनके जीवन के लिए खतरनाक है। लेकिन अत्यन्त कमजोर होने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया है और सामने आकर ऐलान किया है कि वे किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे और अपने समर्थकों के साथ मिलकर संसद तक शान्तिपूर्ण मार्च करेंगे।

6. परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के दुष्परिणाम–लाखों की संख्या में हमारे भारतीय छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें बैठते हैं और फिर जब पेपर लीक की खबर आती है तो वे और उनके माता–पिता सदमे में आ जाते हैं। सालों से की गई मेहनत और पैसे के बर्बाद होने से दुःखी बीस से अधिक होनहार छात्र–छात्राओं ने आत्महत्याएं कीं जो किसी भी समाज के लिए दुःखद है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपने पद पर बने रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। उन्हें तो नैतिक आधार पर ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि शासन की तरफ से भी कोई जिम्मेदाराना बयान अभी तक नहीं आया। इससे स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। निश्चित ही सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होने और आमरण अनशन पर बैठने से न्याय की गुहार लगा रहे छात्रों के इस आंदोलन को एक सार्थक गति मिली है।

7. सोनम वांगचुक ने कहा–एक साक्षात्कार में सोनम वांगचुक ने कहा था ''जनता को जागरूक करना और सत्ता में बैठे लोगों को समझाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप जनता को जागरूक करते हैं तो सरकारों में बदलाव आता है उन्हें जनमत की परवाह होती है, हो सकता है कि उन्हें मेरी सेहत की परवाह ही न हो।''

8. वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर प्रतिक्रियाएं–प्रवासी भारतीयों की संस्था 'हिन्दूज फॉर स्यूमन राइट्स' ने आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिन्ता जताते हुए शिक्षक वर्ग ने कहा है कि ''सरकार को सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए और परीक्षा प्रणाली की अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं पर जवाबदेही तय करते हुये भरोसेमंद प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिये। सोमन वांगचुक से मिलने उनका हाल–चाल लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनके पास जाकर उनसे बात की। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, अभिनेता और अभिनेत्रियां उनसे मिलने पहुंचे।

9. बिगड़ी सेहत के कारण वांगचुक अस्पताल में भर्ती–तेजी से बिगड़ती परिस्थितियों के मद्देनजर 18 जुलाई को वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अस्पताल जाने से एक दिन पहले उन्होंने देश की जनता से रूबरू होकर यह कहा था कि उन्हें विश्वास है कि वे 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे और संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि वांगचुक की इच्छा शक्ति और देश भर के बच्चों का जुनून क्या रंग लाता है। 17 जुलाई को इस आंदोलन में वांगचुक के सहयोग के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि भी सम्मिलित हो गई थीं। (हिफी)

धामी ने दिया चुनाव जीतने का मंत्र

VAगले वर्ष 2027 में पांच राज्यों के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। यहां अब तक भाजपा और कांग्रेस में ही बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे मुकाबला त्रिकोणात्मक होने की संभावना बन रही है। सत्तारूढ़ भाजपा अभी पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्य चेहरा बनाए हुए है जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। उत्तराखण्ड में इस बार एक बड़ा मुद्दा बड़ी संख्या में मतदाताओं को चुनाव से बाहर करना भी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राज्य के करीब 8 लाख मतदाता चुनाव से बाहर हो सकते हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करते हुए डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटा रहा है। इसीलिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में बूथ और मतदाता सूची पर अपना विशेष फोकस कर रखा है। गत दिनों संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एक–एक बूथ और एक–एक वोट पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी बूथ और वोट के महत्व को समझा रहे हैं। उन्होंने मंत्र दिया जहां कम, वहां हम। अर्थात् जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां संगठन को अधिक सक्रिय रहना होगा।

इस बार उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान करीब 8 लाख मतदाताओं के नाम संदेह के घेरे में आ चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी को फिलहाल 'अनकलेटेड' श्रेणी में रखा है। वहीं सत्यापन के दौरान सामने आया है कि इनमें से 1.23 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4.77 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करते हुए अपात्र और डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया में जुटा है। उत्तराखंड में वर्तमान में करीब 80 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। एसआईआर के तहत घर–घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है तो वहीं इस दौरान जिन मतदाताओं की जानकारी सत्यापित नहीं हो पाई, उन्हें अस्थायी रूप से "अनकलेक्टेड" श्रेणी में रखा गया है, हालांकि सत्यापन पूरा होने के बाद योग्य मतदाताओं के नाम बरकरार रहेंगे, जबकि अपात्र पाए जाने वालों के नाम हटाए जा सकते हैं। आयोग का मानना है कि इनमें ऐसे मतदाता भी हो सकते हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं।उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने बूथ और मतदाता सूची पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित कुआंवाला में आयोजित प्रदेश बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एक–एक बूथ और एक–एक वोट पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। तरुण चुग ने प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण है। प्रदेश की जनता पार्टी के साथ खड़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रत्येक समर्थक मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने और उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में अब तक की सर्वाधिक विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का पुराना मिथक टूट चुका है। अब लक्ष्य उत्तराखंड को बीजेपी का अभेद्य राजनीतिक किला बनाने का है।

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। तरुण चुग ने कार्यकर्ताओं से संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं से 'जहां कम, वहां हम' की नीति पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिन बूथों और क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, वहां संगठन को अधिक सक्रियता और मेहनत के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ी विजय दिलाने के लिए चुनाव प्रबंधन की कुशलता को और प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए सही और त्रुटिहीन मतदाता सूची पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उन्होंने पार्टी के बीएलए–2 कार्यकर्ताओं से घर–घर जाकर पात्र नागरिकों को जागरूक करने और तय प्रक्रिया के तहत उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पूरी क्षमता और अनुशासन के साथ निर्वहन करने पर भी जोर दिया।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने का स्पष्ट अर्थ है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में बना न रहे।2022 में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन 2017 की तुलना में 10 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर 33.5 फीसद से बढ़कर 37.9 फीसद हो गया। सबसे बड़ा झटका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगा, जो खटीमा से 6,579 वोटों से हार गए थे। बाद में वे चंपावत उपचुनाव से जीते, लेकिन खटीमा का घाव अब भी ताजा है। खटीमा सीट भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। 2022 में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने 52 फीसद वोट पाकर धामी को हराया। तराई क्षेत्र होने के कारण यहां सिख और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार भी कांग्रेस इस सीट पर मजबूत दावा कर रही है। इसी प्रकार हरिद्वार ग्रामीण सीट पर कांग्रेस की अनुपमा रावत (हरीश रावत की बेटी) ने भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 वोटों से हराया था। 2017 में हरीश रावत खुद यहां हारे थे, लेकिन 2022 में उनकी बेटी ने पार्टी को मजबूत वापसी दिलाई।

युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों पर सरकार जवाब दे : रामबाबू रस्तोगी

कशिश मीडिया

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता रामबाबू रस्तोगी ने केंद्र सरकार पर युवाओं, किसानों, व्यापारियों और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इन ज्वलंत मुद्दों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि देश का युवा लगातार पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान है, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य और राहत की मांग कर रहा है, व्यापारी बढ़ती लागत एवं आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करे।रामबाबू रस्तोगी ने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में लगातार गंभीर चूक हो रही है तो संबंधित केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जनता के समक्ष जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप से ऊपर उठकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य और राहत, व्यापारियों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल, महिलाओं की सुरक्षा तथा महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने दिल्ली में छात्रों एवं प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और छात्र का संवैधानिक अधिकार है। यदि कानून–व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता।समाजवादी पार्टी ने मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए, घायल छात्रों एवं पुलिसकर्मियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से।रामबाबू रस्तोगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और युवाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की घटना को लेकर विभिन्न पक्षों के अलग–अलग दावे सामने आए हैं। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए।

लखनऊ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार भी सीज

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना अलीगंज पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग से कथित दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी सीज कर लिया है।पुलिस के अनुसार, को 16 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि दो नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए तथा उसके साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी।शिकायत के आधार पर थाना अलीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 134ध2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2), 115(2), 351(2), 3(5), 140(4) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5ध6 में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया।पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का बीएनएसएस की धारा 180 के तहत बयान दर्ज कराया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए।मुखबिर की सूचना पर गठित पुलिस टीम ने बंधा रोड के पास से दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जतिन बाजपेई उर्फ छोटू (32 वर्ष) निवासी त्रिवेणीनगर–3, थाना अलीगंज तथा दीपक उर्फ शिवम शुक्ला (33 वर्ष) निवासी त्रिवेणीनगर–3, थाना अलीगंज के रूप में हुई है।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति बलेनो कार (पंजीकरण संख्या यूपी–32 बीके–8317, नीले रंग) को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया है।पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में जतिन बाजपेई के विरुद्ध वर्ष 2021 में जुआ अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज होना सामने आया है, जबकि दीपक उर्फ शिवम शुक्ला के विरुद्ध जुआ अधिनियम के अलावा वर्ष 2026 का एक अन्य आपराधिक मुकदमा भी दर्ज पाया गया है।मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सस्ते माल का झांसा देकर व्यापारी से ढाई लाख रुपये की लूट का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, 1.92 लाख रुपये बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)। मदेयगंज थाना पुलिस ने सस्ते दाम पर डिस्पोजल सामग्री उपलब्ध कराने का झांसा देकर व्यापारी से ढाई लाख रुपये लूटने की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 1.92 लाख रुपये बरामद किए हैं, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।पुलिस के अनुसार, पारा थाना क्षेत्र के मायापुरम, डिप्टीखेड़ा निवासी महेंद्र कुमार एकता नगर चौराहा, ठाकुरगंज में दोना–पत्तल और डिस्पोजल सामग्री की दुकान संचालित करते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम मोहन शेख बताया, उनकी दुकान पर आया और खुद को थोक में पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री का व्यापारी बताते हुए कहा कि उसका गोदाम पक्का पुल, मदेयगंज में है। उसने बाजार से कम कीमत पर करीब 2.50 लाख रुपये का माल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।आरोपी की बातों पर विश्वास कर महेंद्र कुमार 20 जुलाई की सुबह करीब 10रू30 बजे ढाई लाख रुपये लेकर पक्का पुल पहुंचे। वहां आरोपी ने फोन पर उनसे संपर्क कर उन्हें बंधा रोड स्थित संझिया घाट के पास बुलाया, जहां उसके दो अन्य साथी पहले से मौजूद थे। जैसे ही व्यापारी ने मोटरसाइकिल की डिग्गी खोलकर रुपये निकालने का प्रयास किया, तीनों आरोपियों ने उनके हाथ से नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही मदेयगंज थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 96ध2026 धारा 309(2) बीएनएस के तहत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देशन में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई।लगातार की गई कार्रवाई के दौरान को सुबह करीब 11रू30 बजे पुलिस ने पक्का पुल के नीचे गोमती नदी की ओर से तीन आरोपियों मोहन शेख, सोहेल और राकिब को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,92,000 रुपये नकद बरामद किए गए।पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहन शेख ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदारों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने का झांसा देता था। भरोसा जीतने के बाद व्यापारियों को किसी सुनसान स्थान पर बुलाकर उनसे नकदी लूट ली जाती थी। इसी योजना के तहत महेंद्र कुमार को भी बंधा रोड स्थित सुनसान स्थान पर बुलाया गया था।पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात के दौरान गिरोह का एक अन्य सदस्य अनवर दूर खड़ा होकर पुलिस और आने–जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा था। घटना के बाद जब आरोपी लूटी गई रकम का आपस में बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर अनवर रुपयों की एक गड्डी लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि बाकी तीनों आरोपी पकड़ लिए गए।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन शेख (38 वर्ष), मूल निवासी नदिया (पश्चिम बंगाल) हाल निवासी बवाना, दिल्ली, सोहेल (29 वर्ष), मूल निवासी उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) हाल निवासी खदरा, मदेयगंज, लखनऊ तथा राकिब (28 वर्ष), मूल निवासी नदिया (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 309(2) के साथ धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपी अनवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों और राज्यों से भी जुटाई जा रही है।पुलिस का मानना है कि यह गिरोह इसी प्रकार व्यापारियों को कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराने का लालच देकर सुनसान स्थानों पर बुलाता था और योजनाबद्ध तरीके से नकदी लूटकर फरार हो जाता था। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

त्योहारों पर अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाएं, जनहानि की घटना किसी कीमत पर न हो : नितिन अग्रवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब और कच्ची शराब के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कहीं भी जहरीली या अवैध शराब से जनहानि की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए।मंगलवार को लखनऊ के डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान सभागार में आबकारी विभाग की प्रथम त्रैमासिक राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि अवैध शराब की आपूर्ति की किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों में प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।नितिन अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश के सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में शामिल है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश में मदिरा से जनहानि की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को देते हुए कहा कि इसी प्रकार टीम भावना और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते रहना होगा।उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने (ओवररेटिंग) की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।बैठक में विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रदेश सरकार ने 71,278 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून) में विभाग ने 15,809.25 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 14,228.91 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।इसी प्रकार अप्रैल से जुलाई 2026 तक विभाग के लिए 21,800 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,655.23 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का 85.57 प्रतिशत है। वहीं अप्रैल से जुलाई 2025 की तुलना में विभाग का राजस्व संग्रह बढ़कर 100.39 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया है।आबकारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व वृद्धि के साथ–साथ कानून व्यवस्था, जनसुरक्षा और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर त्योहारों के दौरान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को श्रद्धांजलि, समाज ने एक अनमोल रत्न खोया: राघवेंद्र सिंह राजू

लखनऊ (संवाददाता)। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज स्वर्गीय चेतन चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने उन्हें समाज और राष्ट्र का एक अनमोल रत्न बताते हुए उनके व्यक्तित्व और योगदान को याद किया।राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि स्वर्गीय चेतन चौहान से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और कोरोना काल में उनके निधन से समाज ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। उन्होंने कहा कि चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के निर्भीक सलामी बल्लेबाज थे। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा और संघर्षशीलता का परिचय दिया तथा सार्वजनिक जीवन में जनसेवक के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई।उन्होंने कहा कि चेतन चौहान ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि मैदान में संघर्ष कैसे किया जाता है और समाज के लिए समर्पित होकर जीवन कैसे जिया जाता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।राघवेंद्र सिंह राजू ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वर्गीय चेतन चौहान के विचारों और जनसेवा की विरासत को उनके भतीजे एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनुज चौहान आगे बढ़ाएंगे।श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों, समाज के गणमान्य लोगों एवं चौहान परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय चेतन चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को स्मरण किया।

मलिहाबाद पुलिस ने गैर-जमानती वारंट के आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की मलिहाबाद थाना पुलिस ने गैर–जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर–जमानती वारंटों के अनुपालन तथा वांछित एवं वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना मलिहाबाद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में को क्षेत्र भ्रमण, अपराध नियंत्रण, कानून–व्यवस्था ड्यूटी, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग तथा वारंटियों की तलाश के दौरान पुलिस टीम ने ग्राम फिरोजपुर में दबिश देकर एक वारंटी को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्द्रपाल, पुत्र स्वर्गीय महावीर पासी, निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 107ध2007, केस संख्या 1029ध2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 447, 506 तथा वन अधिनियम की धारा 4ध10 के तहत गैर–जमानती वारंट जारी किया गया था।पुलिस ने आरोपी को उसके आवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसे न्यायालय द्वारा जारी वारंट की जानकारी दी गई तथा नियमानुसार उसकी पुत्री को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप संपन्न की गई। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।इस कार्रवाई को उपनिरीक्षक राहुल तिवारी एवं उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह सहित थाना मलिहाबाद पुलिस टीम ने अंजाम दिया।

वन विभाग के ट्री गार्ड चोरी मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ की आड़ में चोरी का सामान खरीदने-बेचने का आरोप

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की महानगर थाना पुलिस ने वन विभाग के आयरन ट्री गार्ड चोरी मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कबाड़ की दुकान की आड़ में चोरी के सामान की खरीद–फरोख्त करने का आरोप है।पुलिस के अनुसार, 20 जून 2026 को शहरी रेंज, लखनऊ के वन रक्षक योगेश कुमार की तहरीर पर थाना महानगर में मुकदमा अपराध संख्या 110ध2026 दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने वन विभाग के 28 आयरन ट्री गार्ड चोरी कर बेच दिए, जबकि मौके से करीब 18 हजार रुपये मूल्य के 10 आयरन ट्री गार्ड बरामद किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण को मिली रिकार्ड रफ्तार, 2017 के बाद 66,838 किमी सड़कें बनीं और लगभग दो हजार पुलों का निर्माण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 के बाद सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के कार्यों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति को नई दिशा मिली है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच पांच वर्षों में प्रदेश में 31,868 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण किया गया था। वहीं 1 अप्रैल 2017 के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 66,838 किलोमीटर तक पहुंच गया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग औसतन 20 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है।सरकार का कहना है कि बेहतर परियोजना प्रबंधन, समयबद्ध क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी के कारण सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आई है। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिला है, जहां बेहतर सड़क संपर्क से किसानों के लिए कृषि उत्पादों का परिवहन आसान हुआ है, स्थानीय बाजारों का विस्तार हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।सड़क निर्माण के साथ–साथ विभाग ने सड़क रखरखाव और नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2012 से 2017 के दौरान जहां 35,843 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया था, वहीं 2017 के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2,93,082 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह लगभग 650 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।वार्षिक औसत के आधार पर भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां प्रतिवर्ष औसतन 7,168 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होता था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 31,413 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। सरकार का दावा है कि सड़क रखरखाव की वर्तमान गति पहले की तुलना में चार गुना से अधिक हो चुकी है।बेहतर सड़क नेटवर्क का प्रभाव स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सेवाओं पर भी पड़ा है। अब एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन दल और अन्य आपातकालीन सेवाएं पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, जिससे समय पर सहायता उपलब्ध होने के साथ जनहानि की घटनाओं में कमी लाने में भी मदद मिल रही है।लोक निर्माण विभाग ने पुल निर्माण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 591 पुलों का निर्माण किया गया था, जबकि 2017 के बाद दीर्घ, लघु और उपरिगामी पुलों की संख्या बढ़कर लगभग दो हजार हो गई है। इस अवधि में पुल निर्माण में करीब तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वार्षिक औसत भी 118 पुल प्रति वर्ष से बढ़कर लगभग 211 पुल प्रति वर्ष हो गया है।सरकार का कहना है कि नए पुलों के निर्माण से उन क्षेत्रों को भी वर्षभर संपर्क सुविधा मिली है, जो पहले बरसात के दौरान कट जाते थे। इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली है और लोगों का समय तथा परिवहन लागत दोनों कम हुई हैं।बेहतर सड़क और पुल नेटवर्क का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। परिवहन लागत घटने से उद्योगों और व्यापार को गति मिली है, कृषि उत्पाद तेजी से बाजार तक पहुंच रहे हैं और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। मजबूत आधारभूत संरचना के कारण औद्योगिक निवेश और नए रोजगार सृजन के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश का सड़क एवं पुल नेटवर्क अब केवल भौतिक संरचना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन और निवेश सहित प्रदेश के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला बन चुका है। मजबूत नेतृत्व, प्रभावी कार्ययोजना और जवाबदेह कार्यसंस्कृति के माध्यम से वर्ष 2017 के बाद जिस गति से सड़क एवं पुल निर्माण कार्य हुए हैं,

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन बना ग्रामीण आत्मनिर्भरता का नया आधार, आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं से बढ़ रही आय व रोजगार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मत्स्य पालन क्षेत्र को तेजी से विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आधुनिक तकनीकों के उपयोग से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी लगातार सृजित हो रहे हैं।राज्य सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालन को कृषि का एक लाभकारी सहायक व्यवसाय बनाकर ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन को रोकना है। इसके लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिले के विकासखंड सण्डवा चंद्रिका के ग्राम कटका मानापुर निवासी रणंजय सिंह ने आधुनिक मत्स्य पालन अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। पारंपरिक खेती से सीमित आय होने के कारण उन्होंने विभागीय प्रचार–प्रसार और समाचार माध्यमों से बायोफ्लॉक तकनीक की जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी लगभग 0.10 हेक्टेयर निजी भूमि पर आधुनिक बायोफ्लॉक प्रणाली के तहत मत्स्य पालन इकाई स्थापित की।इस परियोजना में उन्होंने पंगेशियस प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू किया। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निजी बोरिंग, विद्युत संयोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गईं। कम पानी और सीमित भूमि में अधिक उत्पादन देने वाली यह पर्यावरण–अनुकूल तकनीक उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई।वैज्ञानिक जल प्रबंधन, संतुलित आहार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उनकी इकाई से प्रतिवर्ष औसतन 1.40 टन मछली उत्पादन होने लगा। वर्तमान में इस परियोजना पर लगभग 7 लाख रुपये की वार्षिक लागत आती है, जबकि मछली बिक्री से करीब 18 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार होता है। सभी खर्चों के बाद उन्हें लगभग 6 लाख रुपये की शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके अलावा उनकी इकाई के माध्यम से करीब 10 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है।राज्य सरकार अब पारंपरिक मत्स्य पालन के साथ–साथ बायोफ्लॉक प्रणाली, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और केज कल्चर जैसी आधुनिक तकनीकों को भी बढ़ावा दे रही है। इन प्रणालियों के माध्यम से कम भूमि, सीमित जल और कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो रहा है, जिससे शिक्षित और प्रगतिशील युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं।महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मत्स्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ग्राम सभा के तालाबों के पट्टों के आवंटन में स्थानीय मछुआरा समुदायों, पारंपरिक मत्स्य पालकों और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो रही है।मत्स्य पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और संतुलित आहार पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबंधन, रोग नियंत्रण, वैज्ञानिक पालन और आहार प्रबंधन की जानकारी देकर उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।मत्स्य उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए प्रदेश में कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड वाहनों और आधुनिक मत्स्य बाजारों का नेटवर्क भी विकसित किया जा रहा है।

नाका पुलिस ने दुकानों और वाहनों से माल चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार, करीब पांच लाख रुपये का सामान बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की नाका थाना पुलिस ने दुकानों और वाहनों में रखे माल की चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब पांच लाख रुपये मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया है।

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।पुलिस के अनुसार, थाना नाका में अलग–अलग पीड़ितों की शिकायत पर चोरी के तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। नितीश कुमार की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 125ध2026, गगन प्रसाद की शिकायत पर मुकदमा अपराध संख्या 113ध2026 तथा राम सिंह की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 126ध2026 पंजीकृत किया गया था। तीनों मामलों में अज्ञात चोरों द्वारा दुकानों और वाहनों में रखा माल चोरी करने का आरोप लगाया गया था।घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम के निर्देशन में थाना नाका पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर को दुर्गापुरी झोपड़पट्टी क्षेत्र में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अरविंद फैशंस का कमाल, पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत बढ़कर 27.61 करोड़ रुपये पहुंचा

परिधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अरविंद फैशंस लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 11 प्रतिशत बढ़कर 27.61 करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान कंपनी की परिचालन आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने यह मजबूत प्रदर्शन हासिल किया है।परिधान क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अरविंद फैशंस लिमिटेड (एएफएल) ने चालू वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 27.61 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष 2025–26 की पहली (अप्रैल–जून) तिमाही में कंपनी ने 24.86 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था।शेयर बाजार को दी गई सूचना के मुताबिक, कंपनी की कुल परिचालन आय में भी इस दौरान अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। समीक्षाधीन तिमाही में अरविंद फैशंस की परिचालन आय बढ़कर 1,278.50 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 1,107.31 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। हालांकि, कारोबार के विस्तार के साथ–साथ कंपनी का कुल खर्च भी सालाना आधार पर 1,083.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,245.48 करोड़ रुपये हो गया है।कंपनी के इस मजबूत प्रदर्शन पर अरविंद फैशंस लिमिटेड की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमीषा जैन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत कंपनी के लिए परिचालन प्रदर्शन के लिहाज से काफी मजबूत और उत्साहजनक रही है।अमीषा जैन ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, पेट्रोलियम कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में लगातार आ रही तेजी जैसी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कंपनी का यह प्रदर्शन बेहद उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि यह शानदार नतीजे बाजार में हमारे ब्रांड की मजबूती और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाते हैं।

कंपनी का प्रोफिट 65प्रतिशत उछलकर रु1,057 करोड़ के पार, Revenue में भी रिकार्ड बढ़त

टीवीएस मोटर ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 65 प्रतिशत की शानदार लाभ वृद्धि दर्ज करते हुए अपनी मजबूत बाजार स्थिति को प्रमाणित किया है। परिचालन आय और रिकॉर्ड बिक्री के साथ कंपनी ने प्रतिकूल जिंस कीमतों के बावजूद कुशल लागत प्रबंधन के माध्यम से अपनी लाभप्रदता बनाए रखी है। टीवीएस मोटर वित्तीय परिणाम और ईवी बिक्री वृद्धि इस रिपोर्ट के मुख्य विश्लेषण बिंदु हैं। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 65 प्रतिशत बढ़कर 1,057.61 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025–26 की पहली (अप्रैल–जून) तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 642.86 करोड़ रुपये रहा था। मोटर वाहन कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय बढ़कर 16,295.52 करोड़ रुपये हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 12,210.05 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 11,261.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,894.22 करोड़ रुपये हो गया।टीवीएस मोटर के अनुसार, पहली तिमाही में उसने अब तक की सर्वाधिक तिमाही बिक्री दर्ज की। इस दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कुल बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 16.3 लाख इकाई हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 12.8 लाख इकाई थी। समीक्षाधीन तिमाही में मोटरसाइकिल की बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 7.4 लाख इकाई रही जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 6.2 लाख इकाई थी। स्कूटर की बिक्री पांच लाख इकाई से सालाना आधार पर 36 प्रतिशत बढ़कर 6.8 लाख इकाई हो गई।अंतरराष्ट्रीय कारोबार 33 प्रतिशत बढ़कर 4.7 लाख इकाई पर पहुंच गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 3.5 लाख इकाई था। कंपनी ने कहा कि 2026–27 की पहली तिमाही में उसके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 86 प्रतिशत बढ़कर 1,29,940 इकाई हो गई, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 70,060 इकाई थी।कंपनी के अब 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहक हैं। समीक्षाधीन तिमाही में तिपहिया वाहनों की बिक्री 48 प्रतिशत बढ़कर 66,697 इकाई हो गई जबकि एक वर्ष पहले की समान अवधि में यह 44,978 इकाई थी। कंपनी ने बयान में कहा कि पहली तिमाही में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जिंस कीमतों में तेज वृद्धि का रुख रहा जिससे कच्चे माल आदि की लागत बढ़ी। हालांकि, कीमतों में आंशिक समायोजन तथा लागत अनुकूलन की पहल के जरिये इस बढ़ी हुई लागत के असर को कुछ हद तक कम किया गया।

बाजार में शानदार शुरुआत निवेशकों को मिला करीब 9प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयरों ने बाजार में सकारात्मक शुरुआत करते हुए निर्गम मूल्य पर करीब सात प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है जो इसकी मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाती है। आईपीओ को मिले भारी अभिदान और बेहतर लिस्टिंग गेंस परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के प्रति निवेशकों के अटूट विश्वास को रेखांकित करते हैं।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर अपने निर्गम मूल्य 574 रुपये के मुकाबले करीब सात प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर कंपनी का शेयर 610 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 6.27 प्रतिशत अधिक है। बाद में यह 8.85 प्रतिशत चढ़कर 624.80 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर शेयर ने 613.30 रुपये पर शुरुआत की जो निर्गम मूल्य के मुकाबले 6.84 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,25,845.39 करोड़ रुपये रहा। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को बोली बंद होने तक 41.66 गुना अभिदान मिला था। इसके 9,812.91 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 545–574 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।यह सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित था। मौजूदा शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अमुंडी ने 17.09 करोड़ तक शेयर की बिक्री पेशकश की। वर्ष 1987 में स्थापित एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, 31 मार्च 2026 तक तिमाही औसत प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (क्यूएएयूएम) के आधार पर भारत की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। म्यूचुअल फंड के तहत उसकी 12.51 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां हैं और उसकी बाजार हिस्सेदारी 15.3 प्रतिशत है।

पेटीएम का पहली तिमाही में मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ हुआ, बोनस शेयर का प्रस्ताव फिलहाल टला

पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 220 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी की कर पूर्व आय में भी भारी उछाल आया है, हालांकि बोर्ड ने अभी बोनस शेयर न देने का फैसला लिया है।डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख मंच पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 220 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी ने 203 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) भी दर्ज की है, जो कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है।सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में पेटीएम ने बताया कि अप्रैल–जून तिमाही में उसका परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी की कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) में 182 प्रतिशत का भारी उछाल आया और यह रिकॉर्ड 203 करोड़ रुपये रही, जिससे कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन बढ़कर आठ प्रतिशत हो गया। कंपनी ने इस सफलता का श्रेय व्यापारियों और उपभोक्ता कारोबार में हुई तेज वृद्धि तथा कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित परिचालन दक्षता को दिया है।

यूपीआई बाजार में भी पेटीएम का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। कंपनी का उपभोक्ता यूपीआई सकल लेनदेन मूल्य (जीटीवी) 45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि पूरे उद्योग की औसत वृद्धि दर से 2.2 गुना अधिक है। इस दौरान मासिक आधार पर लेनदेन करने वाले सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी 60 लाख का इजाफा हुआ, जिससे अब यह आंकड़ा आठ करोड़ के पार पहुंच गया है। जून 2026 के अंत तक कंपनी के पास 13,529 करोड़ रुपये का नकद शेष उपलब्ध था।हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन के बीच वन 97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर फिलहाल आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है। कंपनी का मानना है कि इस समय पूरा ध्यान विकास और लाभप्रदता को और अधिक मजबूत करने पर होना चाहिए ताकि शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन किया जा सके। शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद ही विकास की निरंतरता को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है।

कनाडा से आने वाले सामानों पर 50: भारी टैरिफ का ऐलान, नार्थ अमेरिका में छिड़ सकता है महा-ट्रेड वार

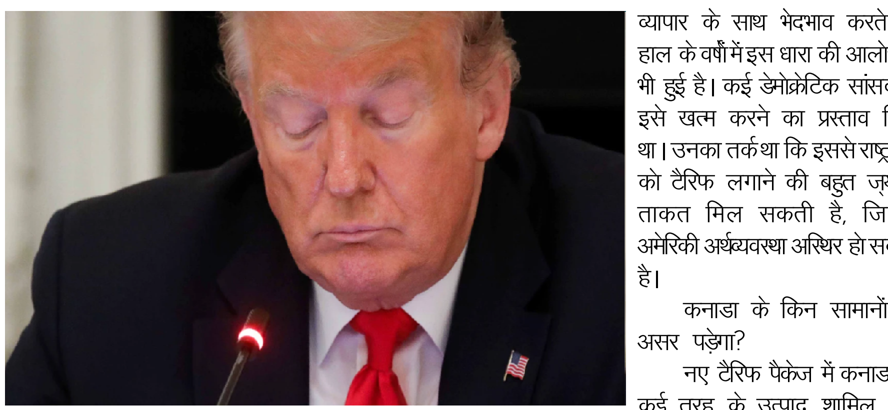

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे कड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए कनाडा से आने वाले अधिकांश सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का बड़ा ऐलान किया है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे कड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए कनाडा से आने वाले अधिकांश सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कनाडा पर ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में अमेरिकी सामानों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह नया टैरिफ आदेश 30 दिनों के बाद लागू होगा, जिससे दोनों देशों के पास औपचारिक बातचीत और समझौते का एक आखिरी मौका बना हुआ है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो इससे नॉर्थ अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच एक दीर्घकालिक और विनाशकारी श्ट्रेड वॉरश (व्यापार युद्ध) शुरू हो सकता है।अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, चीन के अलावा कनाडा उन कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने ट्रंप के पिछले ट्रेड उपायों के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाए थे। श्एसोसिएटेड प्रेसश (।च) की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों को जानकारी देते हुए अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस नए कदम का मकसद ओटावा को उन जवाबी कदमों के लिए जवाबदेह ठहराना है।ट्रंप ने 1930 के अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 338 के तहत तीन अलग–अलग आदेशों पर दस्तखत किए। यह एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की इजाजत देता है जो अमेरिकी व्यापार के साथ भेदभाव करते हैं। हाल के वर्षों में इस धारा की आलोचना भी हुई है। कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। उनका तर्क था कि इससे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की बहुत ज़्यादा ताकत मिल सकती है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है।

कनाडा के किन सामानों पर असर पड़ेगा?

नए टैरिफ पैकेज में कनाडा के कई तरह के उत्पाद शामिल होंगे, जिनमें वे सामान भी हैं जिन्हें पहले ष्–मेक्सिको–कनाडा एग्रीमेंट (न्ैड।) के तहत सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि, कुछ अहम सेक्टर को इससे छूट दी गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि एनर्जी उत्पादों, पोटाश, मछली और जरूरी खनिजों पर टैरिफ लागू नहीं होगा, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप से अहम उद्योगों को बचाया जा सके। यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका ने 2020 के न्ैड। ट्रेड एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया, जिससे नई ट्रेड बातचीत का रास्ता साफ हो गया है जो 2036 तक चल सकती है।

कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी

इस ऐलान से दोनों पड़ोसी देशों के बीच बड़े ट्रेड विवाद की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कनाडा की फेडरल सरकार ने तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने संकेत दिया कि अगर टैरिफ लागू होते हैं, तो ओटावा को कड़ा जवाब तैयार करना चाहिए। फोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा, ष्अगर ये टैरिफ लागू होते हैं तो कनाडा को टैरिफ के बदले टैरिफ और डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाब देना चाहिए।ष्इस बीच, कैनेडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंडिस लैंग ने इस फैसले को ष्अफसोसजनकष् बताया, लेकिन कहा कि 30 दिन की लागू होने की अवधि का इस्तेमाल औपचारिक बातचीत के जरिए सार्थक प्रगति करने के लिए किया जाना चाहिए।अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक अनिश्चितता की चेतावनी दी

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ष्है कि इन टैरिफ के नतीजे नॉर्थ अमेरिका से बाहर भी हो सकते हैं। कैटो इंस्टीट्यूट में जनरल इकोनॉमिक्स के वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट लिंसिकॉम ने कहा कि इस कदम से इंटरनेशनल ट्रेड में काफी अनिश्चितता पैदा होती है। लिंसिकॉम ने कहा, ष्हमने श्रूबीकॉनश पार कर लिया है (यानी एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता)। धारा 338 का इस्तेमाल ट्रंप के टैरिफ के लिए श्न्यूक्लियर ऑप्शनश जैसा है।ष् एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि नए टैरिफ से सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए लागत बढ़ सकती है, और फाइनेंशियल मार्केट में और ज़्यादा उतार–चढ़ाव आ सकता है।ट्रंप के लिए राजनीतिक जोखिम भी बढ़ रहे हैं

टैरिफ के फैसले का ट्रंप के लिए घरेलू राजनीतिक असर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका नवंबर में होने वाले मिड–टर्म चुनावों की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल षलिबरेशन डेष् पर टैरिफ की घोषणाओं से बाजार में जबरदस्त उतार–चढ़ाव आया था, क्योंकि महंगाई बढ़ने और मंदी की आशंका थी। इससे प्रशासन को बातचीत जारी रहने के दौरान अपना रुख कुछ समय के लिए नरम करना पड़ा था।इस साल फरवरी में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ट्रंप के पास आर्थिक आपातकाल घोषित करके कुछ टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं था। उस फैसले के बाद, प्रशासन ने नए इंपोर्ट ड्यूटी लागू करने के लिए धारा 338 समेत दूसरे कानूनी प्रावधानों का सहारा लेना शुरू कर दिया।टैरिफ असल में इंपोर्ट किए गए सामान पर लगने वाले टैक्स होते हैं। हालांकि ट्रंप का हमेशा से यह तर्क रहा है कि इनसे कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका लाने के लिए बढ़ावा मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अब तक इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है।टैरिफ के ये नए उपाय ऐसे समय में आए हैं जब महंगाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। इंपोर्ट की बढ़ती लागत और ईरान से जुड़े टकराव के कारण तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए कीमतें और बढ़ सकती हैं।

टाटा स्टील झारखंड में करेगी 10,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार

टाटा स्टील ने झारखंड में साल 2028 तक विभिन्न परियोजनाओं में 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इस निवेश के माध्यम से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।टाटा स्टील ने झारखंड में औद्योगिक विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए साल 2028 तक 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के इस कदम से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी कुल स्टील निर्माण क्षमता को मौजूदा 2.73 करोड़ टन सालाना से बढ़ाकर चार करोड़ टन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टाटा स्टील अपनी क्षमता विस्तार के साथ–साथ कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन के तरीकों को अपनाने पर जोर दे रही है। कंपनी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक कुशल विनिर्माण प्रक्रियाओं को लागू करना चाहती है।परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी देते हुए कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इस कुल निवेश में से 7,000 करोड़ रुपये हिसार्ना और सरल गलन (स्मेलटिंग) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में लगाए जाएंगे। ये आधुनिक प्रौद्योगिकियां इस्पात उद्योग में उत्पादन को अधिक पर्यावरण–अनुकूल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपयोग की जाती हैं।

मैड्रिड में Spain World Cup Victory का भव्य जश्न, 20 लाख प्रशंसकों के साथ सड़कों पर उतरा जनसैलाब

स्पेन की विश्व कप जीत ने राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित किया है, जिसका प्रमाण मैड्रिड में उमड़ी 20 लाख लोगों की ऐतिहासिक भीड़ है। फेरान टोरेस के निर्णायक गोल ने न केवल दूसरा विश्व खिताब दिलाया, बल्कि स्पेनिश खेल संस्कृति की वैश्विक श्रेष्ठता को भी रेखांकित किया है। स्पेन की विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम सोमवार को जब स्वदेश लौटी तो लगभग 20 लाख लोग अपने प्रिय खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए मैड्रिड की सड़कों पर एकत्रित हुए थे। स्पेन के सभी 26 खिलाड़ियों और उसके कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने न्यूजर्सी में फाइनल में अर्जेंटीना को 1–0 से हराने के एक दिन बाद मैड्रिड पहुंचने पर देश के शाही परिवार और फिर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। सांचेज ने कहा, "आपके खेल की शानदार शैली, बेहतरीन प्रयास और जीत के लिए बहुत–बहुत बधाई। हमें आपको खेलते हुए देखकर वाकई बहुत आनंद आया।" इसके बाद पूरी टीम एक खुली छत वाली बस में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए मैड्रिड की सड़कों पर निकल गई।बस पर लिखा था "सितारे एक साथ चमकते हैं" और उस पर खिलाड़ियों की तस्वीरें भी लगी हुई थीं। खिलाड़ियों के हाथों में विश्व कप ट्रॉफी थी और उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी उस पर स्पेनिश में लिखा था 'सोमोस कैम्पियोनेस' यानी 'हम चैंपियन हैं'। खिलाड़ी पूरी परेड के दौरान नाचते–गाते और प्रशंसकों से बातचीत करते रहे। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने परेड शुरू होने से पहले कहा, "ऐसे जोशीले और समर्पित प्रशंसकों वाले एक अद्भुत देश का प्रतिनिधित्व करना भावनात्मक और गौरवपूर्ण अनुभव रहा है। हम बहुत खुश हैं।" यह परेड प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास मोनक्लोआ पैलेस के पास से शुरू हुई और मैड्रिड की सड़कों से होते हुए सिबेल्स स्क्वायर तक गई, जहां उन्होंने एक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया और अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इसमें लगभग 120,000 लोग मौजूद थे।चौक पर बने मंच पर प्रवेश करने से पहले खिलाड़ियों का एक–एक करके परिचय कराया गया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अपने प्रवेश के समय बजाए जाने वाले गीत का चयन किया।

Hockey World Cup के लिए Harmanpreet Singh के नेतृत्व में 20 सदस्यीय Team India का ऐलान, क्या खत्म होगा 50 साल का सूखा?

भारत ने अगले महीने होने वाले एफआईएच पुरूष हॉकी विश्व कप के लिये 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है जिसमें प्रो लीग का यूरोप चरण खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। प्रो लीग में 24 सदस्यीय टीम चुनी गई थी लेकिन विश्व कप में 20 सदस्यों की टीम ही चुनी जानी है। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविचंद्र सिंह मोइरांगथाम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ति टीम में जगह नहीं बना सके हैं।भारत पिछले महीने प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद चार जीत, पांच ड्रॉ और सात हार के बाद नौ टीमों में पाकिस्तान से ऊपर आठवें स्थान पर रहा। आठ बार की ओलंपिक चौम्पियन भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक बार 1975 में विश्व कप जीत सकी है।पिछली बार भुवनेश्वर में हुए 2023 विश्व कप में मेजबान भारत नौवें स्थान पर रहा था। भारत ने बार्सीलोना में 1971 में कांस्य और एम्सटर्डम में 1973 में रजत पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाले हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे।

अपना दल एस अल्पसंख्यक मंच की कार्यकारिणी घोषित

फतेहपुर। अपना दल एस के अल्पसंख्यक मंच की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिलाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत बनाने और बूथ स्तर तक विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। अल्पसंख्यक मंच की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ममनून खान एवं मोहम्मद रफीक को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सैयद उवैस, नौशाद खान, अब्दुल्ला, शाहनवाज, राहुल, विनय, नौशाद और राजू को जिला कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को गांव–गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने अल्पसंख्यक मंच के जिलाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान को निर्देश दिए कि शेष कार्यकारिणी का गठन शीघ्र पूरा कर संगठनात्मक गतिविधियों को और गति दी जाए। बैठक के साथ आयोजित जनसुनवाई में जिला उपाध्यक्ष पदम सिंह पटेल ने लोगों की समस्याएं सुनीं। संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया सचिव पप्पू वर्मा, जिला उपाध्यक्ष पदम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आईटी मंच विपिन कौशल, जिलाध्यक्ष श्रमिक मंच दीपू पटेल, जिला उपाध्यक्ष ममनून खान, जिला सचिव लईक अहमद सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसपी से मिला सीजेए का प्रतिनिधिमंडल, संवाद गोष्ठी की उठाई मांग

- पुलिस-मीडिया की भूमिका पर चर्चा का दिया प्रस्ताव

फतेहपुर। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन (सीजेए) ने जनपद में पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर पत्रकारों के साथ संवाद गोष्ठी आयोजित करने की मांग की है।सीजेए के राष्ट्रीय महासचिव शीबू खान ने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र में कहा कि संगठन पत्रकारों के हितों, सुरक्षा और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि वर्तमान समय में समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों को अनेक प्रकार की व्यावहारिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुलिस विभाग भी संवेदनशील परिस्थितियों में कानून–व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच नियमित संवाद और आपसी समन्वय समय की आवश्यकता बन गया है। एसपी से अनुरोध किया कि पत्रकारों के साथ भी एक विशेष संवाद गोष्ठी आयोजित की जाए। संगठन का कहना है कि यदि पत्रकार और पुलिस आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो समाज तक सही, तथ्यपरक और जिम्मेदार सूचनाएं पहुंचाने के साथ–साथ अपराध नियंत्रण और जनजागरूकता के अभियानों को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय महासचिव श्री खान ने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि सुविधानुसार तिथि एवं समय निर्धारित कर इस संवाद गोष्ठी का आयोजन कराया जाए, ताकि जनपद के पत्रकार इसमें भाग लेकर अपने सुझाव एवं समस्याएं साझा कर सकें और पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में सार्थक पहल हो सके। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शहंशाह आब्दी, प्रदेश उपाध्यक्ष जरेयाब खान, जिला संरक्षक वसीम अख्तर, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, जिला सचिव एवं कार्यालय प्रभारी धीर सिंह यादव, लखनऊ युवा जिलाध्यक्ष मुहाफिज आब्दी सहित कई लोग मौजूद रहे।

स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिले का जलवा

फतेहपुर। कानपुर स्थित स्वीट एंजल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित दो दिवसीय स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ फतेहपुर की शाखा राज ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पदकों पर कब्जा जमाकर जिले का गौरव बढ़ाया। टीम ने प्रतियोगिता में दो स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए।प्रतियोगिता में अर्जित नारायण पाण्डेय और अनुष्का यादव ने स्वर्ण पदक, कविश कुमार, इशिता यादव और रक्षा त्रिपाठी ने रजत पदक, जबकि इशिता सोनी और हर्ष चक्रवर्ती ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता से लौटने पर ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ फतेहपुर के अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने सभी विजेता खिलाड़ियों का विजय तिलक लगाकर, पदक पहनाकर तथा टी–शर्ट भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। एसोसिएशन के सचिव एवं प्रशिक्षक राजकुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशिक्षण में नई तकनीकों और आधुनिक अभ्यास पद्धति को शामिल कर खिलाड़ियों को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि वे आगामी प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ जीत का उत्साह मनाया, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया।

वर्षों से उपेक्षित है इसौली विधानसभा

विकास कार्यों के नाम पर मिलता है आश्वासन

कुड़वार सुल्तानपुर। वर्ष 2012 के परिसीमन बाद बनी इसौली विधानसभा विकास कार्यों के लिए उपेक्षा का शिकार हो रही है।आम जन से जुड़ी समस्याओं का कोई भी जन प्रतिनिधि निदान नहीं करवा पा रहा है। बता दे कि विगत वर्षों में बढ़ती जनसंख्या व आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय विकास खंड के बहलोलपुर गांव में 132 केवीए पावर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव के बाद राजस्व विभाग ने जमीन उपलब्ध कराकर विद्युत विभाग को सौप दी। लेकिन आज तक उसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। सांसद मेनका गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1998 में भाजपा कार्यकाल में स्थापित 33 केवी पावर हाउस का लोड कम करने के लिए सरकौड़ा पावर हाउस की स्थापना तो करा दी गई लेकिन 33 हजार की जो लाइन 400 पयागीपुर से आती है उसी से कुड़वार के साथ ही इसका भी संचालन शुरू हो गया। अन्ततः आए दिन ओवर लोड के चलते 33 हजार की लाइन फाल्ट में चली जाती है। जिसका खामियाजा विद्युत निविदा संविदा कर्मचारियों के साथ साथ लाखों आबादी को भुगतना पड़ता है जिले से मात्र 12 किमी की दूर बसे ब्लॉक मुख्यालय कस्बे पर आए दिन बिजली की समस्या रहती है।साथ ही कस्बे की बात करे तो अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम की स्थिति रहती है जिस पर कभी भी विभागीय अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती है।विकास खंड क्षेत्र के ऊंचगांव में भी 33 केवीए पावर हाउस प्रस्तावित है लेकिन बस कागजों में। जमीन पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है। क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों की बात करे तो कुड़वार अलीगंज मार्ग अभी भी सिंगल ग्रामीण सड़क है। इसको चौड़ीकरण के लिए स्थानीय विधायक ने प्रस्ताव दिया।लेकिन चुनाव वर्ष आ जाने के बाद भी अभी तक कार्य नहीं शुरू हो सका।जबकि इस सड़क की मांग पूर्व सांसद मेनका गांधी के कार्यकाल में भी होती रही है। गर्मी के मौसम में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जिला मुख्यालय से ही आती है। जब तक पहुंचती है तब तक काफी नुकसान हो जाता है।कई दशक पहले जिले के सांसद रहे स्व डीबी राय ने गर्मी के महीने में स्थानीय थाने पर एक फायर ब्रिगेड वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कराई थी लेकिन सत्ता व समय परिवर्तन के साथ वह भी खत्म हो गई। अभी हाल फिलहाल में फायर ब्रिगेड बनाने के लिए भी कुड़वार ग्राम पंचायत के जमीन चिन्हित करके बैनामा भी गई है लेकिन इस अमली जामा कब पहनाया जाएगा।यह भविष्य के गर्त में है।

विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 1450 किलो लहन नष्ट

सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को जिले में व्यापक कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त, अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बल्लीपुर एवं चुनहा में दबिश दी।कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक रण विजय सिंह (क्षेत्र–1), अरुण कुमार (क्षेत्र–4) एवं नेहा श्रीवास्तव (क्षेत्र–5) सहित आबकारी विभाग के स्टाफ तथा कोतवाली नगर पुलिस की टीम शामिल रही। संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए। टीम ने मौके से करीब 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि लगभग 1450 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।अभियान के दौरान क्षेत्र की संचालित आबकारी दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। साथ ही गुप्त रूप से टेस्ट परचेज कर नियमों के अनुपालन की जांच की गई।इसके अलावा कबाड़ियों की दुकानों एवं ईंट–भट्ठों की भी सघन चेकिंग की गई।टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के निर्माण और सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की।

सुरक्षा से सशक्तिकरण की ओर बढ़ा स्पेक्ट्रम ग्रुप

'मिशन शक्तिव साइबर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान आयोजित'

कूरेभार/सुल्तानपुर। अद्वैत फाउंडेशन द्वारा संचालित स्पेक्ट्रम ग्रुप के तत्वावधान में छात्र–छात्राओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।मुख्य अतिथि के रूप में कूरेभार थानाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान की जानकारी देते हुए छात्राओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा विषम परिस्थितियों में पुलिस की सहायता प्राप्त करने के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस प्रशासन हर समय आमजन की सहायता के लिए तत्पर है।कार्यक्रम में पुलिस टीम ने साइबर सुरक्षा पर विशेष सत्र आयोजित कर विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने तथा सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (वुमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 102व108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 1930 (साइबर हेल्पलाइन) के महत्व और उपयोग की विस्तृत जानकारी भी दी।संस्थान की ओर से प्रबंधक आनंद सावरण, एचआर मैनेजर अनूप मिश्र, ऑपरेशनल मैनेजर ज्योति शर्मा, विवेक वर्मा, अभिषेक पाण्डेय, विनय सिंह, दीप्ती साहू, सुशील चौधरी, विख्यात दत्त मिश्र, रूचि पाण्डेय एवं मंजू लता सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संस्थान प्रबंधन ने पुलिस टीम का स्वागत करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

समरथपुर/पड़रे गंदानाला सफाई पर उठे सवाल

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील बल्दीराय क्षेत्र के समरथपुर से पड़रे तक लगभग पांच किलोमीटर लंबे गंदानाले की सफाई को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सफाई कार्य केवल पुल और पुलियों के आसपास कराकर पूरे नाले की सफाई का दावा कर दिया गया, जबकि अधिकांश हिस्से में आज भी झाड़–झंखाड़ और गाद जमा है, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है।ग्रामीणों के अनुसार कागजों में पूरे नाले की सफाई दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान किए जाने की आशंका है। उन्होंने आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि यदि पूरे नाले का निष्पक्ष स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है लेकिन यदि उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो यह नीति पर सवाल खड़े करता है और शासन की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। स्थानीय लोगों ने पूरे नाले का भौतिक सत्यापन, भुगतान अभिलेखों तथा माप पुस्तिका (एमबी) की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मिश्रित तहसील कार्यसमिति का हुआ गठन

मिश्रिख, सीतापुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के संरक्षक भरत त्रिपाठी व जिला प्रभारी उमेश शुक्ला की सहमति से जिलाध्यक्ष विभूति पुरी ने जिला महामंत्री गोविन्द सहाय गुप्ता वागीश दिनकर बाजपेई सहित सम्पूर्ण कार्यसमिति की राय से मिश्रित नगर कार्यसमिति व मिश्रित तहसील कार्यसमिति का गठन किया।उन्होंने अपने उद्बोधन में नई कार्यसमिति को व्यापारियों के हर सुख दुख में खड़े रहने की सलाह दी। नई कार्यकारिणी में यतीन्द्र बब्लू अवस्थी को संरक्षक कमलाकांत मिश्रा को नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को तहसील अध्यक्ष बनाया गया। नगर कार्यसमिति में प्रशांत कुमार सिंह को नगर महामंत्री सोमांश मिश्रा, आलोक सिंह, विश्वजीत वर्मा,जयंकर गुप्ता को नगर उपाध्यक्ष तथा नगर मंत्री में केशव त्रिवेदी, विशाल मिश्रा, हिमांशु सोनी व विजेंद्र वर्मा की नियुक्ति की गई श्याम प्रकाश वर्मा को नगर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई चंदन त्रिवेदी मीडिया प्रभारी गौरव सिंह (गोलू) को सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। नगर संगठन में सदस्य के रूप में अनिल वर्मा, प्रियांशु शर्मा, अभिषेक शुक्ला, सोमदत्त प्रताप सिंह, हरिश्च वर्मा, अच्युत कुमार, शिवेश चंद्र वैश्य, रवि शंकर, मोहन गुप्ता, इन्द्र गुप्ता व अमित वर्मा की नियुक्ति की गई। वहीं तहसील कार्यसमिति में अजय शुक्ला को तहसील महामंत्री, जगजीवन मिश्रा, शशांक पांडे सोनू, मुकुल दीक्षित, ष्णा रस्तोगी, विनय मिश्रा और अंकुर मिश्रा को तहसील उपाध्यक्ष बनाया गया। मनोज पाण्डेय, मुनीश गाजी, आकाश अवस्थी, संजय गई। दिनेश सिंह यादव को तहसील कोषाध्यक्ष शुभम शुक्ला व अभिषेक अवस्थी को तहसील मीडिया प्रभारी व गौरव सिंह व शुभम दीक्षित को सोशल मीडिया का कार्य सौंपा गया। तहसील कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हरीश मराठा, दिलीप मिश्रा, अनूप वर्मा, विक्की मिश्रा, प्रमोद तिवारी, सोनू तिवारी, ससम गुप्ता, चेतराम कश्यप, मोहित गुप्ता, अमित सिंह, शुभांशु मिश्रा, पारुल त्रिवेदी, हरिकेश गुप्ता, अजय दीक्षित, श्याम, शशांक मिश्रा, पंकज मिश्रा, विनोद शुक्ला, कुलदीप मिश्रा, गोलन शुक्ला और हेमू गुप्ता की नियुक्ति की गई। जिलाध्यक्ष विभू पुरी ने नवीन दायित्वधारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे ये आशा की कि वे संगठन के प्रति निष्ठावान रहते हुए संगठन को ऊंचाइयों पर ले जायेंगे और व्यापारियों के हितों की रक्षा करेंगे। अमित सैनी, दीपांकल दीक्षित को तहसील मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी

हैदराबाद नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप,सभासदों ने एडीएम को ज्ञापन दिया

उन्नावसंवाददाता उनगर पंचायत हैदराबाद में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मंगलवार को सभासदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कान्हा गौशाला, पेयजल परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ज्ञापन में सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत की कान्हा गौशाला में गौवंशों की देखभाल में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। कमजोर और बीमार पशुओं को समय पर चारा, पानी और उपचार नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, मृत पशुओं के निस्तारण में भी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन अनियमितताओं के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया है। सभासदों ने पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्यों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी नलकूप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रति नलकूप पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आरोप है कि इन परियोजनाओं में निम्न गुणवत्ता की मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पिछले लगभग छह माह से नगर पंचायत की बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई है।

इसके कारण सभासदों को जनसमस्याएं उठाने और विकास कार्यों पर अपनी राय रखने का अवसर नहीं मिल रहा है। सभासदों का आरोप है कि कई कार्य उनकी सहमति और हस्ताक्षर के बिना ही कराए जा रहे हैं।

दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

उन्नावसंवाददाता नगर कांग्रेस कमेटी गंगाघाट के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार दोपहर करीब दो बजे दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मयंक बाजपेयी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मयंक बाजपेयी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र पेपर लीक, रोजगार और अन्य मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन उन पर कथित तौर पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं। बाजपेयी ने कहा कि छात्रों के प्रति अपनाया गया यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि पार्टी छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है और उनकी आवाज को बुलंद करती रहेगी। प्रदर्शन में बाबूलाल गुप्ता, विश्वनाथ दास, पिंटू तिवारी, निर्मल बाजपेयी, अकबाल अवस्थी, संजय सिंह, मोहम्मद हनीफ, विचित्र वीर सिंह, रंगीलाल शर्मा, दीपक कश्यप, अर्जुन बाजपेयी, प्यारेलाल, बुद्धिलाल विश्वकर्मा, रामचेतन भास्कर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

संकुल धरैंचा की संकुल शिक्षक बैठक सम्पन्न

- ब्लाक को सबसे अग्रणी ब्लाक बनाना है : एआरपी

खैराबाद, सीतापुर। शासन की मंशानुसार खैराबाद ब्लॉक के समस्त संकुलों में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना के दिशा निर्देशन में किया गया। इसी क्रम में संकुल कासिमपुर में उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित प्रवक्ता मनीष पांडेय ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मिश्र उपाध्यक्ष आशीष मिश्र उपस्थित रहे इसी प्रकार सभी दस संकुलों में बैठकों का आयोजन किया गया। संकुल धरैंचा की जुलाई माह की संकुल बैठक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरैंचा में संपन्न हुई। इस अवसर पर एआरपी वीरेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।बैठक मासिक एजेंडा के अनुसार संचालित की गई संकुल शिक्षकों द्वारा विभाग द्वारा प्राप्त एजेंडे के आधार पर गतिविधि कराई गई। बच्चों को सीखने की लय में लाने के लिए तथा विज्ञान किट के उपयोग और स्मार्ट क्लास, टैबलेट आईसीटी लैब के प्रभावी उपयोग, पोर्टल पर अपलोड समय सारणी के अनुसार कक्षाएं व गतिविधियां, इको क्लब, रिमीडियल शिक्षण कैचअप, नवोदय विद्यालय प्रवेश फॉर्म भरने तथा बच्चों को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों और यूनिफार्म आदि के सम्बन्ध में तथा मौखिक भाषा विकास संबंधी खेल गतिविधियों आदि पर चर्चा की गई। विद्यालयों के सर्वांगीण एकेडमिक अभ्यास पर चर्चा की गई। नोडल संकुल शिक्षक काजिम हुसैन तथा संकुल शिक्षक हसन जमाल रिजवी ने विस्तार से बताया। संकुल शिक्षक एजाज अहमद मुदित पाण्डेय फैजुल हसन ने कहा कि हम सब साथी शिक्षक टीम भावना से कार्य करेंगे तो प्रगति होगी और अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताए उसका निस्तारण किया जाएगा। एआरपी वीरेन्द्र कुमार ने सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि अपने अपने विद्यालयों में शिक्षक डायरी अवश्य बनाएं और नियमित उसी के अनुसार कार्य करें जो भी कार्य करें पूरी तरह गुणवत्ता पूर्ण ढंग से करें तथा अपने कार्यों को सबसे पहले पूरा किया करें तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। निपुण आंकलन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शत प्रतिशत आवश्यक रूप से करवाना आवश्यक है क्योंकि यह जिलाधिकारी की प्रथम वरीयता में एक है। बैठक का शुभारंभ एआरपी वीरेन्द्र कुमार, मुदित पांडेय द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। बैठक में संकुल धरैंचा के 108 शिक्षकों के सापेक्ष 25 शिक्षक मौजूद थे। इसी अवसर पर सभी संकुल शिक्षकों द्वारा डीसीएफ भी भरा गया। बैठक का संचालन संकुल शिक्षक काजिम हुसैन ने किया। बैठक के अंत में प्रभारी प्रधानाध्यापिका फिरोजा बानो ने आभार व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि अगस्त माह की बैठक पूर्व माध्यमिक विद्यालय हुसैनपुर कैमहरा में और सितंबर माह की प्राथमिक विद्यालय कैमहरा हुसैनपुर में आयोजित होगी।

दुधवा में जंगली मशरूम खोदते दो गिरफ्तार, 20 किलो बरामद

लखीमपुर–खीरीसंवाददाता दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रतिबंधित वन क्षेत्र से अवैध रूप से धरती का फूल (जंगली मशरूम) खोद रहे दो लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 20 किलोग्राम धरती का फूल बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के अनुसार, मानसून के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व में धरती का फूल और कटरुआ बड़ी मात्रा में उगते हैं, जो वन्यजीवों के प्राकृतिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाजार में इनकी ऊंची कीमत मिलने के कारण कुछ लोग बिना अनुमति घने जंगलों में प्रवेश कर इनका अवैध संग्रह करते हैं। इससे वन्यजीवों के भोजन पर प्रतिकूल असर पड़ता है और मानव–वन्यजीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाता है। मंगलवार को दक्षिण सोनारीपुर रेंज के गुलरा प्रक्षेत्र में वन दरोगा अनुराग, वन रक्षक भानू यादव और बीट वाचरों की टीम नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान उप प्रभागीय वनाधिकारी बेलरायां दीपक कुमार पांडेय और क्षेत्रीय वन अधिकारी दक्षिण सोनारीपुर अखिलेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे। गश्त के दौरान ग्राम मटैहिया, थाना मझगई, तहसील पलिया निवासी 40 वर्षीय छड़ीराम पुत्र लालजी और 35 वर्षीय मंशाराम पुत्र नारायण को जंगल में धरती का फूल खोदते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वन कर्मियों ने दोनों के कब्जे से करीब 20 किलोग्राम धरती का फूल बरामद कर उन्हें हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक धरती का फूल जंगल में प्राकृतिक रूप से उगने वाला दुर्लभ वन उत्पाद है, जिसका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। स्थानीय बाजार में इसकी कीमत 250 ग्राम के लिए 200 से 300 रुपये तक मिल जाती है, जिसके चलते इसकी अवैध तस्करी और संग्रह की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

गेम आन, स्टाइल आन! लार्ड्स में भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान जाह्नवी कपूर का पावरफुल फैशन स्टेटमेंट

जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर मौके पर अपने फैशन सेंस से लोगों का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। अभिनेत्री हाल ही में लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आनंद लेने पहुंचीं, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था।

इस खास मौके पर जाह्नवी ने राल्फ लॉरेन का टेलर्ड ब्लेजर और मैचिंग ट्राउजर पहनकर क्लासिक एलिगेंस और मॉडर्न पावर ड्रेसिंग का शानदार मेल पेश किया। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और सिग्नेचर स्लीक हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया, जिससे उनके आउटफिट का शार्प सिल्हूट और भी उभरकर सामने आया।

जहां क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मैदान पर चल रहे रोमांचक मुकाबले पर टिकी थीं, वहीं स्टैंड्स में मौजूद जाह्नवी कपूर ने अपने बेहतरीन फैशन चॉइस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह शानदार लुक लॉर्ड्स के शाही और ऐतिहासिक माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है।

रेड कार्पेट हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम, जाह्नवी कपूर हर बार अपने स्टाइल से एक नया फैशन गोल सेट करती हैं। भारत–इंग्लैंड मैच के दौरान उनका यह एलिगेंट और पावरफुल लुक एक बार फिर साबित करता है कि किसी भी मौके पर फैशन के खेल में जीतना उन्हें बखूबी आता है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस और गंगाजल जैसी ब्लाकबस्टर फिल्में देने के बाद क्यों बालीवुड से दूर हुई ग्रेसी सिंह

ग्रेसी सिंह का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल है, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी सादगी, सहज अभिनय और दमदार किरदारों के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इस फिल्म में आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और उनकी मासूम अदाकारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। हालांकि, शानदार शुरुआत और कई सफल फिल्मों के बावजूद ग्रेसी सिंह धीरे–ध ीरे बॉलीवुड से दूर होती चली गईं। ग्रेसी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में की थी। वह द प्लैनेट्स डांस ग्रुप के साथ कई स्टेज शो और टूर का हिस्सा रहीं। इसके बाद उन्होंने 1997 में टीवी सीरियल अमानत से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। छोटे पर्दे पर पहचान बनाने के बाद उन्हें आशुतोष

गोवारिकर की फिल्म लगानरू वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया में काम करने का मौका मिला। आमिर खान द्वारा निर्मित इस फिल्म में ग्रेसी ने गौरी का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। लगान न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, बल्कि इसे ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भी नामांकन मिला। यह सम्मान पाने वाली मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद तीसरी भारतीय फिल्म बनी। इस सफलता के बाद ग्रेसी सिंह बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।

इसके बाद उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, गंगाजल और अरमान जैसी फिल्मों में काम किया। मुन्ना भाई एमबीबीएस और गंगाजल को बड़ी सफलता मिली, लेकिन अरमान बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी न ह ी उ त र सकी। इसके बाद उनकी कई फिल्में, जैसे चंचल, देशद्रोही और देख भाई देख, लगातार फ्लॉप होती रहीं। इन असफलताओं का असर उनके करियर पर साफ दिखाई दिया और उन्हें बॉलीवुड में पहले जैसी पहचान नहीं मिल सकी।

हिंदी फिल्मों में सफलता कम होने के बाद ग्रेसी सिंह ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। हालांकि, वहां भी उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ग्रेसी ने कई इंटरव्यू में कहा है कि अभिनय उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य कभी नहीं था और न ही उन्हें सुपरस्टार बनने की कोई विशेष इच्छा थी।

साल 2015 में उन्होंने टीवी शो संतोषी मां से छोटे पर्दे पर वापसी की। इस धारावाहिक में देवी संतोषी मां के रूप में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया और नई पीढ़ी के बीच भी उन्हें पहचान मिली।

समय के साथ ग्रेसी सिंह आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारीज से गहराई से जुड़ गईं। वह अक्सर आध्यात्मिक जीवन, आत्मसंतोष और प्रसिद्धि से परे सच्ची खुशी की बात करती हैं। ग्रेसी सिंह अभी भी अविवाहित हैं और फिल्मों की चकाचौंध से दूर एक शांत, संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि सफलता केवल शोहरत में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतुष्टि में भी छिपी होती है।

तारा शर्मा ने फिल्म में काम करने के लिए छोड़ दी थी नौकरी

अपनी पहली फिल्म ओम जय जगदीश के 24 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस तारा शर्मा ने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए लंदन में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें इस बदलाव को लेकर घबराहट हो रही थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरी पहली फिल्म की शूटिंग में कितना मजा आया था। आज 24 साल हो गए इसके बाद उन्होंने अल्का याग्निक और सोनू निगम के गाने चोरी चोरी के बारे में बात की, जो उन पर और अभिषेक बच्चन पर फिल्माया गया था।उन्होंने लिखा, हमारे गाने चोरी– चोरी की एक झलक, शानदार पहले को–एक्टर बनने और मुझे इतना सहज महसूस कराने के लिए धन्यवाद। खासकर इसलिए क्योंकि आप लगातार मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, हाहा! इससे मुझे तब बहुत मदद मिली, जब मैं डांस स्टेप्स गलत होने से डरी हुई थी। बहुत खुशी है कि आपको एक्टिंग के लिए वो तारीफ मिल रही है जिसके आप हकदार हैं। उन्होंने अनुपम खेर का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने 2002 की इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। अनुपम खेर जी, मुझे इस फिल्म में कास्ट करने के लिए ध न्यवाद। आपके साथ फिल्मों में एक्टिंग का सफर शुरू करने के लिए मैं आभारी हूं। तारा ने आगे कहा, हमारी साथ की दूसरी फिल्मों, जैसे खोसला का घोसला 1 और 2 के दौरान भी, मैं अक्सर आपसे सलाह लेती हूं और आपके टैलेंट, पॉजिटिविटी, ह्यूमर और शब्दों के खेल में महारत की तारीफ करती हूं। तारा ने बाकी शानदार कास्ट और क्रू का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, लंदन में कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर पेड़ों के आस–पास डांस करना– यह उस फर्क को दिखाने का मेरा थोड़ा मजाकिया अंदाज है।

उर्वशी रौतेला की ट हिडलेस्टन से मुलाकात, विंबलडन जमी बालीवुड-हाली की जुगलबंदी

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने हाल ही में विंबलडन 2026 मेन्स में हॉलीवुड स्टार टॉम हिडलेस्टन से मुलाकात की। अभिने मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने और हॉलीवु सिनेमा के बारे में काफी दिलचस्प बातें कीं। अभिनेत्री ने बताया, 2026 मेन्स फाइनल में जाना मेरे लिए एक यादगार अनुभवों था। इटैलियन टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर और जर्मन टेनि अलेक्जेंडर जेवरेव को सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करते दे में प्रेरणा देने वाला था। अभिनेत्री ने दोनों खिलाड़ियों के बारे में हुए बताया, उनके जुनून, अनुशासन और खेल भावना ने सभी दिलाया कि विंबलडन टेनिस का शिखर क्यों बना हुआ है। शानदार जीत और अलेक्जेंडर को शानदार प्रदर्शन के लिए

अभिनेत्री ने बातचीत में जोड़ा कि टॉम हिडलेस्टन से मि दिन और भी यादगार बन गया। उन्होंने कहा, हमने पारंपरिक स्ट्रॉबेरी और क्रीम का मजा लेते हुए सिनेमा के बारे में बहुत अच्छ की। मैंने हमेशा उनके काम की तारीफ की है, खासकर लोकी किरदार और उन्हें कैरेक्टर के विकास, उनके क्रिएटिव प्रोसेस रोल के प्रति उनके डेडिकेशन के बारे में बोलते हुए सुनना बहुत था।अभिनेत्री ने बताया, हमने मार्वल के अलावा उनके कुछ बेहत पर भी बात की, जिसमें द नाइट मैनेजर, क्रिमसन पीक, और उन थिएटर परफॉर्मेंस शामिल हैं। उनकी विनम्रता, समझदारी, अ कहने के जुनून ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। यह लंदन की एक दोपहर थी जिसमें एक ही जगह पर खेल, सिनेमा, और कल्चर मनाया गया। विंबलडन सच में एक टाइमलेस अनुभव है, औ ऐसा दिन है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी।अभिनेत्री हाल ही में एक्शन–कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आई थी। य फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जो अपने शानदार निर्देशन और स कास्ट के लिए जानी जाती है।

निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज करने की थ्रोबैक फोटो की शेयर, लिखा-8 साल पहले उसने कहा था हां

सिंगर–अभिनेता निक जोनस ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जोनस को प्रपोज करने के आठ साल पूरे होने के मौके पर पुरानी यादें ताजा कीं। निक ने रविवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रपोजल नाइट की एक थ्रोबैक सेल्फी साझा की है। तस्वीर में निक कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रियंका अपने चेहरे का कुछ हिस्सा हाथ से छिपाते हुए अपनी चमकदार सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर के साथ निक ने कैप्शन में लिखा, 8 सालों पहले उसने हाँ कहा था, साथ में रिंग का इमोजी भी लगाया।

निक की इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने यह पूछा

गौरतलब है कि निक जोनस ने 19 जुलाई 2018 को प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया था। इसके लिए उन्होंने लंदन में टिफनी एंड कंपनी का पूरा स्टोर बंद कराकर उनके लिए परफेक्ट इंगेजमेंट रिंग चुनी थी।

हिन्दी दैनिक विजडम इंडिया
स्वामी,मुद्रक एवं प्रकाशक श्री शील कुमार शुक्ला द्वारा हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा लि0 ,94, एम0जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ से छपवाकर 633/387,गेहमर कुंज कालोनी, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
सम्पादक–शील कुमार शुक्ला
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ मान्य होगा।